साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

آوازِ تسنیم

tasneemtv.official@gmail.com

PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | वर्षः 02 / अंकः 17 | जयपुर, रविवार, 15 नवंबर , 2026 | पृष्ठः 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन

भारत समिटः महिला राइडर की बाइक पर बैठे राहुल गांधी, बोले गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है भाजपा

एजेंसी। हैदराबाद

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बाइक रैली में शामिल हुए। हैदराबाद में आयोजित यह बाइक रैली शिल्पाकला वेदिका से शुरू हुई। राहुल गांधी ने नोवोटेल के पास गिग वर्कर्स को संबोधित किया। वह भारत समिट 2026 में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात हैदराबाद पहुंचे थे और नोवोटेल होटल में ठहरे हुए थे। हैदराबाद पहुंचने पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया।



फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा को घेरा

राहुल गांधी की ओर से लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर सचिन एम. सावंत ने भाजपा पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में पेगासस विवाद का भी जिक्र किया। सावंत ने सवाल उठाते हुए कहा, 'यह भाजपा का काम करने का तरीका है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा महाराष्ट्र में भी हो चुका है। वह घोटाला सबके सामने था। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि सच है। वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं।'

'गिग वर्कर्स मोबाइल पर देख सकेंगे कमाई का पूरा ब्योरा'

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा का युग है। आज देशभर में डेटा की चर्चा हो रही है और डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप और उबर जैसी कंपनियां डेटा के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन अब तक भारत में गिग वर्कर्स को अपने ही डेटा तक पहुंच नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि नया कानून गिग वर्कर्स को अपने डेटा पर अधिकार देगा। तेलंगाना सरकार उन्हें यह गारंटी दे रही है कि उनके द्वारा किए गए काम, पूरी की गई राइड और उसके बदले मिलने वाले भुगतान का पूरा ब्योरा उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा।

कांग्रेस गिग वर्कर्स को भागीदार बनाना चाहती है: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी विचारधारा गिग वर्कर्स एवं मजदूरों को देश की नींव मानती है। कांग्रेस उन्हें केवल श्रमिक नहीं, बल्कि देश के विकास में भागीदार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स को बीमा, प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर आर्थिक सहायता और आराम करने के लिए समर्पित स्थान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी गिग वर्कर्स के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे मजदूरों को सेवक और बंधुआ श्रमिक बनाकर उनके अधिकारों को कुचलना चाहते हैं।

गिग वर्कर्स के साथ खड़ी है कांग्रेस: सचिन सावंत

इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन एम. सावंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के निचले तबके के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज के निचले तबके के लोगों के साथ रही है। चुनाव प्रचार और चुनावी घोषणापत्र में हमने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है। हम अपने वादे पूरे करते हैं; हम 'जुमलों' में विश्वास नहीं करते।'

रैली से पहले नोवोटेल होटल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

रैली में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले नोवोटेल होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाई-प्रोफाइल सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वॉड ने पूरे इलाके की जांच की। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी गई।

गिग वर्कर्स के लिए योजनाओं का राहुल गांधी ने किया शुभारंभ

हैदराबाद के हाइटेक सिटी स्थित जयभेरी ग्राउंड में राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।

गिग वर्कर्स से किया वादा पूरा कर रही कांग्रेस: राहुल गांधी

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां और दर्द साझा किया था। उस समय उन्होंने गिग वर्कर्स से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम उनकी मांगों पर जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही उनकी मदद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी अपने उसी वादे को पूरा कर रही है।

गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे वाई-फाई सुविधाओं वाले रेस्ट जोन: राहुल गांधी

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स तेलंगाना के शहरों में तेज धूप के बीच सामान की डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार हैदराबाद समेत राज्य के सभी शहरों में वाई-फाई सुविधाओं से लैस रेस्ट जोन स्थापित करेगी। इन केंद्रों पर गिग वर्कर्स अपने वाहन पार्क कर सकेंगे और बैठकर आराम करने के साथ जरूरत पड़ने पर सो भी सकेंगे।

गिग वर्कर्स को हर डिलीवरी पर मिलेगा 1% अतिरिक्त राशि: राहुल गांधी

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी ने एलान किया कि तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की गारंटी दे रही है। उन्होंने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि गिग वर्कर्स को हर डिलीवरी के प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत राशि अतिरिक्त मिलेगी। यह रकम कंपनियों को तेलंगाना के हर शहर में देनी होगी। यह पैसा पहले गिग वर्कर्स बोर्ड के पास पहुंचेगा और फिर सीधे गिग वर्कर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

मेहनत का फायदा अंबानी-अडानी जैसे अरबपतियों को मिल रहा

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा-आरएसएस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। भाजपा-आरएसएस की विचारधारा गिग वर्कर्स और मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जहां वे 24 घंटे मेहनत करें, दुर्घटनाओं में घायल हों या जान गंवाएं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा अंबानी-अडानी जैसे अरबपतियों और उबर-ओला जैसी कंपनियों को मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था में मेहनतकश लोगों को उनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल रहा है।



होर्मुज: बारूदी सुरंगों का जाल, टैंकर में लगी आग ईरानी नौसेना बोली, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे तो यही होगा

एजेंसी। नई दिल्ली

ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की टैंकरों को चेतावनी दी है। ईरानी दावों के मुताबिक, प्रतिबंधित रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर नौसैनिक बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर आग का शिकार हुए। ईरान ने जहाजों को अपने ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से समन्वय और निर्धारित नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। वहीं, अमेरिका और इज़राइल के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रीय संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूसरी ओर, बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम को नष्ट करने के ईरान के दावे को सेंटकॉम ने खारिज किया है।

ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके गुजरने का आरोप

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईएसएनए के अनुसार, नौसेना ने बताया कि टैंकर ने प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय अपनी ट्रैकिंग और पहचान प्रणालियां बंद कर दी थीं। नौसेना ने इस क्षेत्र को असुरक्षित और प्रतिबंधित घोषित किया है। शनिवार को जारी बयान में चेतावनी दी गई कि यदि कोई अन्य टैंकर इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नौसेना ने जहाज मालिकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासनों पर भरोसा करके अपनी संपत्ति खतरे में डालने का आरोप लगाया। ये घटनाक्रम ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सामने आए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर ईरानी नौसेना का निशाना

आईएसएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी नौसेना के जनसंपर्क विभाग ने कहा, 'यह अफसोस की बात है कि टैंकर मालिक अन्य लापरवाह जहाजों के हश्र से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। वे अमेरिकी राष्ट्रपति की बेतुकी बातों पर भरोसा करके अपनी पूंजी को बारूदी सुरंगों वाले युद्ध क्षेत्र में भेज रहे हैं और उसे आग में झोंक रहे हैं।' वहीं, कुछ घंटे पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने भी दावा किया था कि दो तेल टैंकर बिना अनुमति के दक्षिणी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वे नौसैनिक बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गए, जिससे उनमें विस्फोट हुआ और आग लग गई।

राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास को लेकर अहम बैठक

प्रदेश में निवेशकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

प्रदेश में रोजगार सृजन एवं राजस्व अर्जन का केन्द्र बन रहा राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन

राजस्थान के औद्योगिक विकास को मिल रही अभूतपूर्व गति

3 महीने में पूर्ण हो आवंटन प्रक्रिया और 6 महीनों में औद्योगिक इकाई का संचालन

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने के साथ ही रोजगार सृजन एवं राजस्व अर्जन का प्रमुख केन्द्र बन रहा है। इस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण एवं उनका उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से औद्योगिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिल रही है। पेट्रोकेमिकल जोन के सुनियोजित विकास से प्रदेश में निवेश के और नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री शनिवार को राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश एवं उपलब्ध संभावनाओं के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोन के विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए इसे निवेशकों के लिए आकर्षक औद्योगिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक भूखंडों का आवंटन केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आवंटित भूखंडों पर निर्धारित समयावधि में वास्तविक औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ होना भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया आगामी तीन माह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। आवंटन प्राप्त करने के छह माह के भीतर औद्योगिक इकाई की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शेष उपलब्ध भूखंडों का आवंटन शीघ्र नीलामी के माध्यम से करने तथा पूर्व में भूखंड आवंटित होने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि का उपयोग वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के लिए हो तथा निवेश के नाम पर भूखंडों का अनावश्यक रूप से उपयोग लंबित नहीं रखा जाए।

स्थानीय स्तर पर उत्पादन हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोकेमिकल जोन का विकास इस दृष्टि से किया जाए कि रिफाइनरी से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग प्रदेश में ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जा सके। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ ही उद्योगों की लागत एवं आपूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की संभावनाएं विकसित होंगी। उन्होंने सीमेंट, पाइप सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उपयोग की संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रदेश में इन उत्पादों की वर्तमान मांग, उपभोग एवं भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करवाने पर जोर दिया।

उन्होंने इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत उद्यमियों एवं संबंधित औद्योगिक इकाइयों संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में उद्यमियों की आवश्यकताओं, मांगों एवं सुझावों पर विचार कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि स्थानीय उद्योगों को जोन से जोड़कर मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

निवेशकों की बैठक आयोजित कर आकर्षित करें निवेश

मुख्यमंत्री ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित कर राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को रिफाइनरी से उपलब्ध होने वाले बाय-प्रोडक्ट्स का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए रिफाइनरी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का हों प्रभावी क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए समय-समय पर निवेश सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना एवं प्लग एंड प्ले सहित अन्य निवेश संवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिकाधिक निवेशकों एवं उद्यमियों तक पहुंचे तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन का विकास प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर उत्पादन, निवेश विस्तार और रोजगार के नए अवसरों के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, उद्योग विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।



आईएनएस चिल्का में 3,358 अग्निवीर और नाविकों की पासिंग आउट परेड, 142 महिलाएं शामिल

भुवनेश्वर , एजेंसी। ओडिशा के आईएनएस चिल्का में भव्य पासिंग आउट परेड (पीओपी) आयोजित की गई, जिसमें रिकॉर्ड 3,358 प्रशिक्षुओं ने अपना गहन प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें 142 महिला प्रशिक्षु भी शामिल थीं। इस समारोह के साथ भारतीय नौसेना के 2,756 अग्निवीरों, 286 चिकित्सा सहायकों और भारतीय तटरक्षक बल के 316 नाविकों ने 16 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण पूरा किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इस पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया, जबकि दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक अध्ययन, शारीरिक फिटनेस, तैराकी, और नेतृत्व विकास सहित विभिन्न गतिविधियों में निपुण बनाया गया। इस दौरान अनुशासन, टीम भावना तथा नौसेना के मूल मूल्यों - कर्तव्य, सम्मान और साहस पर विशेष जोर दिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नचिकेता सनासम को एसएसआर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु, अरबाज अमीन को एमआर श्रेणी में और दीक्षा को समग्र योग्यता सूची में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रशिक्षु चुना गया। अमर शक्ति एम को सर्वश्रेष्ठ नाविक जीडी तथा अर्पित सांगवान को सर्वश्रेष्ठ नाविक डीबी का सम्मान मिला। इस यादगार अवसर पर युवा प्रशिक्षुओं के परिवारों ने भी भव्य परेड का अवलोकन किया।

पाकिस्तानी एजेंट को साझा कीं गोपनीय सैन्य सूचनाएं

- वायुसेना विंग कमांडर पर देशद्रोह का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सैन्य जानकारी और युद्ध योजनाओं से संबंधित दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र (चार्जशीट) में इस चौंकाने वाले खुलासे ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हैरान करने के साथ-साथ सतर्क कर दिया है। आरोप है कि यह अधिकारी कथित तौर पर हनीट्रैप का शिकार हुआ था और उसे अश्लील तस्वीरों के बदले देश की सुरक्षा से जुड़ी अत्यधिक संवेदनशील जानकारियां साझा करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ। आरोपपत्र के अनुसार, विंग कमांडर ने व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को सैन्य अभियानों से संबंधित गोपनीय सूचनाएं, युद्ध की रणनीतियों से जुड़े दस्तावेज, ड्रोन तकनीक से संबंधित विस्तृत जानकारियां और सैन्य तैनाती का विस्तृत ब्योरा भेजा था। इसमें अग्रिम मोर्चे के लड़ाकू विमानों की गतिविधियों और संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों के भौगोलिक निर्देशांक भी शामिल थे, जो दुश्मन देश के हाथों में जाने से बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन सूचनाओं को किसी विदेशी ताकत के साथ साझा करना न केवल देशद्रोह के समान माना जाता है बल्कि इसके अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे देश की सामरिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स से डिस्चार्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें बुधवार को सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ मिनट तक बेहोश रहने के बाद उन्हें सुरक्षाकर्मी शुरुआत में घर ले गए थे, लेकिन बाद में एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में लाया गया, जहां हृदय रोग विभाग की देखरेख में उनकी जांच और उपचार किया गया। यह पिछले दो वर्षों में उनका सबसे लंबे समय तक बेहोश रहने का मामला था। इसके पहले वह जून 2025 में नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान और इस साल जनवरी में दो बार अपने घर पर भी बेहोश हो चुके हैं। मार्च 2025 में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स के आईसीयू में भर्ती किया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी। धनखड़ ने अगस्त 2022 से जुलाई 2025 तक भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

मैं ओवैसी तेरे आंगन का...पवन खेड़ा ने एआईएमआईएम और चंद्रशेखर के गठबंधन पर कसा तंज

चंद्रशेखर ने कांग्रेस और सपा को दिया था गठबंधन का प्रस्ताव

नई दिल्ली , एजेंसी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू किया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने ओवैसी पर फिल्मी अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ में एक नई पिक्चर बन रही है, जिसका नाम है मैं ओवैसी तेरे आंगन का।

कांग्रेस नेता खेड़ा ने अपनी टिप्पणी में पुरानी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का जिक्र कर कहा, वहां पिक्चर थी ना मैं तुलसी तेरे आंगन की, अब लखनऊ में एक नई पिक्चर बन रही है मैं ओवैसी तेरे आंगन का। उनके इस बयान को



ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

इसके पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी दोनों नेताओं के गठबंधन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच हुआ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के इशारे पर तैयार किया गया है। कांग्रेस सांसद तिवारी का दावा था कि बीजेपी इसतरह के गठबंधनों के जरिए विपक्षी दलों के वोटों में बंटवारा कराने की रणनीति अपनाती है।

उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के सीमांचल क्षेत्र का उदाहरण देकर कहा था कि इसतरह के राजनीतिक समीकरणों से चुनाव में वोटों का विभाजन होता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने भी गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों दलों के साथ सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद ओवैसी और चंद्रशेखर ने साथ आने का फैसला किया। अब इस गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

खरगोन में आया 4.5 तीव्रता का भूकंप, खंडवा के कई इलाकों में भी हिली धरती

- भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था, कोई जनहानि नहीं

भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश के खरगोन, खंडवा और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजकर 15 मिनट 28 सेकंड पर खरगोन क्षेत्र में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र 21.59डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75.552डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। ये स्थान धार जिले के धामनोद से करीब 69 किलोमीटर दक्षिण और इंदौर से करीब 129 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में बताया गया है। भूकंप के झटके खरगोन जिले और खंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई है। भूकंप की गहराई कम होने के कारण केंद्र के आसपास के इलाकों में कंपन महसूस होने की संभावना रही। खंडवा जिले और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं जिसमें 12 सितंबर 2025 को सुबह करीब 8:46 बजे खंडवा में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर था। 4 जून 2025 को रात करीब 9:57 बजे खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर में 3.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र खंडवा से करीब 66 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा के पास, अमरावती के नजदीक बताया गया था। 21 जून 2024 को सुबह 9:04 बजे खंडवा और पंधाना क्षेत्र में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसका केंद्र खंडवा के आसपास जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

एनसीपी के दोनों गुटों का नहीं होगा विलय, एनडीए में शामिल हो सकते हैं शरद पवार

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई,(ईएमएस)। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय की अटकलों पर अब विराम लग गया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, शरद पवार का गुट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने का विकल्प तलाश रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) बिना किसी विलय के ही एनडीए का हिस्सा बनने की संभावनाएं खंगाल रहा है। पहले ऐसी खबरें थीं कि दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा संकेतों से यह संभावना क्षीण होती दिख रही है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार



को दिल्ली में इस बात को साफ करते हुए कहा, विलय की चर्चा उसी पल खत्म हो गई थी जब मेरे भाई (अजीत पवार) ने पार्टी छोड़ी थी। यह बयान विलय की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाता है।

सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार का गुट एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल होने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर यह गुट एक अलग घटक दल के रूप में एनडीए में शामिल होता है, तो उन्हें केंद्र में कोई अहम मंत्रालय और राज्य मंत्रिमंडल में भी कोई पद मिल सकता है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय से पार्टी विधायकों को फोन किए गए हैं ताकि उनका रुख और मौजूदा राजनीतिक हालात पर उनकी राय जानी जा सके। इस बातचीत के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या दोनों गुटों का विलय होना चाहिए या अन्य विकल्प तलाशे जाने चाहिए। एनसीपी (अजीत गुट) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, दोनों गुटों के विलय के खिलाफ हैं। उन्होंने महायुति के प्रदेश नेतृत्व को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और चेतावनी दी है कि विलय से उनके अपने गुट के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा पवार ने यह भी संकेत दिया है कि अगर शरद पवार का गुट एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर एनडीए में शामिल होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

कराची में 7 महीने से फंसे 6 नाविक, भारत ने पाकिस्तान से मांगी मदद

नई दिल्ली , एजेंसी । पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले करीब सात महीनों से छह भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। इनमें भारतीय मर्चेंट नेवी के एक चीफ ऑफिसर भी शामिल हैं। परिवारों की लगातार अपील और नाविकों की स्वदेश वापसी में हो रही देरी के बीच भारत सरकार ने अब पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर सहायता मांगी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इसकी पुष्टि की। हालांकि, इस मामले में एक बड़ी पेचीदगी सामने आई है। भारत सरकार के मुताबिक, नाविकों की परेशानी सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विवाद से नहीं, बल्कि जहाज की मालिक कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक विवाद से जुड़ी है। यही वजह है कि नाविकों की वापसी में लगातार देरी हो रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार वहां फंसे नाविकों, उनकी शिपिंग कंपनी और कंपनी के एजेंट के संपर्क में है। उन्होंने पाकिस्तान से कांसुलर सहायता का अनुरोध किए जाने की पुष्टि की। जायसवाल ने कहा, हम वहां मौजूद इन लोगों के संपर्क में हैं, साथ ही उनके नियोक्ता यानी पोत परिवहन कंपनी और उनके एजेंट से भी बातचीत कर रहे



हैं, और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानी पक्ष से राजनयिक सहायता का भी अनुरोध किया है। रिपोर्टों के मुताबिक, छह भारतीय नाविकों का जहाज 17 अप्रैल 2023 (मूल खबर में 2026 दिया गया था, जिसे 2023 किया गया है) को कराची बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद जहाज एक विवाद में उलझ गया और चालक दल के सदस्य वहीं फंसकर रह गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा का नाम सामने आया है, जो ईरान की कंपनी के साथ काम कर रहे थे। परिवार के मुताबिक, जहाज के कराची पहुंचने के बाद कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसका खामियाजा जहाज पर मौजूद भारतीय कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में एक अहम तकनीकी और कानूनी पहलू बताया। उनके मुताबिक, जहाज पर तैनात कर्मचारी अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी जगह दूसरे चालक दल की व्यवस्था करना जरूरी है। जब तक कंपनी नए कर्मचारियों को नहीं भेजती, तब तक मौजूदा चालक दल के सदस्यों के लिए जहाज से औपचारिक रूप से विदा लेना मुश्किल है। इस बीच, नाविकों के परिवारों ने उनकी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विनीत किशोर मिश्रा के परिवार का आरोप है कि जहाज पर मौजूद कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, और बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। परिवारों के मुताबिक, जहाज पर संचार व्यवस्था बेहद खराब है, जिससे नाविकों की अपने परिजनों से नियमित बातचीत नहीं हो पा रही है। कई बार करीब 15 दिनों में एक बार ही उनसे संपर्क हो पाता है। सरकार इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

सीएम मान को पाकिस्तान के न्योते पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा- राष्ट्रीय नीति का पालन करें सभी

लाहौर में विश्व पंजाबी सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनने का मिला निमंत्रण

नई दिल्ली ,एजेंसी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाले 'विश्व पंजाबी सम्मेलन' में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है और सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश जाने वाले जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों को राजनीतिक मंजूरी देने के मामले में मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के तहत आकलन करता है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख सभी के सामने स्पष्ट है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को पाकिस्तान आने का औपचारिक तथा मौखिक निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि यह निमंत्रण पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी दिया गया है। सम्मेलन लाहौर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

एफएटीएफ बैठकों में भारत की सक्रिय भागीदारी- जायसवाल ने बताया कि भारत ने पेरिस में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की पूर्ण बैठक और कार्य समूह की बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। भारत ने इन बैठकों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए होने वाली फंडिंग को रोकने वाले वैश्विक तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लिया।

दिल्ली के प्रदूषण में बायोमास और कार्बनिक एयरोसोल की 50.8 फीसदी रही हिस्सेदारी

-आईआईटीएम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, धुआं प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा

लखनऊ , एजेंसी। नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के प्रदूषण के स्रोतों के आकलन के मुताबिक बायोमास जलाना और द्वितीयक कार्बनिक एयरोसोल गुरुवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण रहे। इन दोनों में से प्रत्येक का शहर के कुल प्रदूषण में 25.4 फीसदी योगदान रहा। वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा, जिसका योगदान 17 फीसदी था।

वहीं, द्वितीयक अकार्बनिक एयरोसोल का प्रदूषण में योगदान 11.8 फीसदी रहा। द्वितीयक अकार्बनिक एयरोसोल में नाइट्रेट का योगदान 4.9 फीसदी, अमोनिया का 4.1 फीसदी और सल्फेट का 2.9 फीसदी रहा। द्वितीयक कार्बनिक एयरोसोल हवा में मौजूद बेहद छोटे ठोस कणों या तरल बूंदों को कहते हैं, जो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि वायुमंडल में कई गैसों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। मिश्रित ईंधन दहन से 10.7 फीसदी प्रदूषण हुआ, जबकि पटाखों का योगदान 7.1 फीसदी रहा। नगरपालिका के कचरे और प्लास्टिक और रबर युक्त कचरे को जलाने से 1.5 फीसदी प्रदूषण हुआ। वहीं, खनिज धूल और राख का योगदान 0.9 और औद्योगिक उत्सर्जन का 0.2 फीसदी रहा।

विशेषज्ञों ने बताया कि द्वितीयक कार्बनिक एयरोसोल वायुमंडल में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। इनका स्रोत कुछ उद्योगों, डीजल और पेट्रोल वाहनों तथा बायोमास जलाने से होने वाला उत्सर्जन हो सकता है। दिल्ली में गुरुवार को धुंध की मोटी भूरी परत में लिपटी रही। इससे शहर की इमारतें और दूर तक का नजारा धुंधला नजर आया। हवा की गुणवत्ता और खराब होने से लोगों को खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वच्छ हवा के बुनियादी अधिकार की मांग को लेकर शहरभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बीच दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई बुधवार के 313 से बढ़कर गुरुवार को 350 पर पहुंच गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

दिवाली के बाद प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत रहे पटाखों का योगदान 7.1 फीसदी रह गया। सोमवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में पटाखों का योगदान 71.1 फीसदी और मंगलवार को 29.8 फीसदी था। बुधवार को यह 7.4 फीसदी रहा। दिल्ली के लिए निर्णय सहायता



प्रणाली के मुताबिक शुक्रवार को परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण का योगदान बढ़कर 18.5 फीसदी होने का अनुमान है। इसके शुक्रवार को प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है।

परिसीमन और महिला आरक्षण कानून पास करने के लिए विशेष सत्र बुला सकती हैं मोदी सरकार

केंद्रीय मंत्रियों का दावा पास करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद

नई दिल्ली, एजेंसी । केंद्र सरकार संसद का एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिसीमन और बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण कानून से जुड़े विधेयकों को जल्द से जल्द पारित कराना है। यह संभावित सत्र आगामी शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित किया हो सकता है, जो 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू होने की संभावना है।बीजेपी सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार के पास अभी भी एक छोटा विशेष सत्र आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय है। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में संकेत दिया था कि विधायी पैकेज को पारित करने के लिए दो विकल्प हैं.....या एक विशेष सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएं। हालांकि, पहले बीजेपी के सहयोगी दलों को संकेत दिया गया था कि इस शीतकालीन सत्र में पारित करने की अधिक संभावना है।

इन विधेयकों को पारित कराना मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने की दिशा में आखिरी मौका हो सकता है। 2029 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। इस विधायी पैकेज में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख है, जो कि परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए एक जटिल संख्याबल की जरुरत होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग-अलग पारित करना होता है, जिसके लिए कुल सदस्यता के बहुमत के साथ-साथ मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की अनिवार्य शर्त होती है। इसतरह के विधेयकों को संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं किया जा सकता। इसी जटिलता के चलते, अप्रैल में संख्याबल की कमी के कारण एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था।

वर्तमान संख्याबल पर और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 155 है। यदि सभी सांसद मतदान में भाग लेते हैं, तब दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 मतों (जो वर्तमान संख्या से 40 कम हैं) और राज्यसभा में 161 मतों (जो 6 कम हैं) की आवश्यकता होगी।

हालांकि, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने आत्मविश्वास जताकर दावा किया है कि मोदी सरकार के पास आवश्यक आंकड़े से लगभग 15 वोट अधिक हैं। केंद्र सरकार विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने और उनका समर्थन या कम से कम मतदान से गैरहाजिरी सुनिश्चित करने की कोशिश में है।

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, सरकार को सत्र बुलाने के लिए 14 दिनों के अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी, और वह किसी भी दिन बैठक बुला सकती है। यह विशेष सत्र के आयोजन की संभावना को और प्रबल करता है, जहां सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी में की पूजा-अर्चना, क्षेत्र में सुरक्षा पर विशेष ध्यान

कटरा, एजेंसी । जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में रियासी जिले में स्थित त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा कर पूजा-अर्चना की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, उनका यह दौरा क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड संख्या के बीच विशेष महत्व रखता है। उपराज्यपाल की यात्रा से ठीक एक दिन पहले, पुलिस उपमहानिरीक्षक (उधमपुर-रियासी रेंज) स्वर्ण सिंह कोतवाल ने रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकुंद तिबरेवाल के साथ श्रद्धालुओं के आधार शिविर कटरा का दौरा किया था। उन्होंने कटरा से भवन तक जाने वाले दोनों यात्रा मार्गों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का गहन जायजा लिया था। इस बीच, माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ रही है।

सैम पित्रोदा ने कहा, मेरा फोन और लैपटॉप टैप किया जा रहा... मोदी खुद स्क्रूड्राइवर लेकर ऐसा नहीं कर रहे

नई दिल्ली, एजेंसी । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा ने हाल ही में दावा किया है कि उनका फोन और लैपटॉप टैप किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्क्रूड्राइवर लेकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह बयान राहुल गांधी के उन आरोपों के बीच आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना मोबाइल फोन टैप करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने बताया कि उनकी टैपिंग के पीछे किसका हाथ है।

पित्रोदा ने जोर दिया कि निजी रिश्तों को राजनीति से अलग रखना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके और उनकी पत्नी के प्रति गर्मजोशी और अपनापन रखते हैं। उनका मानना है कि वे किसी से असहमत होने के बावजूद उसके साथ कॉफी पी सकते हैं, यह दिखाता है कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक व वैचारिक मतभेद अलग-अलग हैं। पित्रोदा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके निजी संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक और वैचारिक मतभेद कायम हैं।

इस संदर्भ में उन्होंने 12 नवंबर को दिवाली और गुजराती नववर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी



ने सोशल मीडिया पर पित्रोदा को सैम भाई कहकर संबोधित किया था और उनकी पत्नी अंजना बेन के लिए भी सुखद व स्वस्थ वर्ष की कामना की थी। इसके जवाब में पित्रोदा ने भी मोदी को नरेंद्र भाई कहकर धन्यवाद दिया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की थी। पित्रोदा ने साफ किया कि शुभकामनाओं का यह आदान-प्रदान किसी भी तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से सैम पित्रोदा और नरेंद्र मोदी के बीच एक निजी बातचीत थी।



प्रलयः रणवीर की फिल्म की शूटिंग पर उठे सवाल

रणवीर सिंह अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि उनकी फिल्म की शूटिंग पर विवाद हो रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने महाराष्ट्र खेल विभाग की तरफ से फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के आजाद मैदान को इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे इस खेल मैदान का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शूटिंग की वजह से अंडर-14 और अंडर-16 इंटर-स्कूल मैचों को टालना पड़ा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीए ने खेल विभाग के उप-निदेशक को पत्र लिखकर पूछा है कि व्यावसायिक अनुमति देने से पहले एसोसिएशन से सलाह क्यों नहीं ली गई। एमसीए एपेक्स काउंसिल के सदस्य नदीम मेमन ने बताया कि खेल विभाग युवा खिलाड़ियों की जरूरतों के बजाय व्यावसायिक बुकिंग को ज्यादा अहमियत दे रहा है।

मैदान पर अतिक्रमण का इल्जाम

मेमन ने कहा, 'आजाद मैदान का एक बड़ा हिस्सा पहले ही मेट्रो के निर्माण कार्य के लिए दे दिया गया था, मगर कई बार याद दिलाने के बावजूद ठेकेदारों ने अभी तक वह जगह खाली नहीं की है। मुंबई पुलिस भी अपनी मूल जगह पर वापस जाने के बजाय अभी भी मैदान पर कब्जा जमाए हुए है। अब यहां फिल्मों की शूटिंग की भी अनुमति दी जा रही है।'

मेमन ने उठाए सवाल

मेमन ने बताया कि फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग के लिए मैदान पर बड़े-बड़े सेट लगाए गए और खेलने वाली सतह पर कृत्रिम घास बिछा दी गई। आजाद मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड है, न कि कोई व्यावसायिक जगह। धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों, मैराथन और प्रदर्शनियों की वजह से पहले भी यहां खेल गतिविधियों में रुकावटें आई हैं। मेमन ने सवाल उठाया कि युवा टूर्नामेंटों में आने वाली रुकावटों की जिम्मेदारी कौन लेगा? एमसीए ने अपने आधिकारिक पत्र में खेल विभाग से आग्रह किया है कि वे पहले से तय खेल आयोजनों को प्राथमिकता दें। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि उनके अंडर-14 और अंडर-16 टूर्नामेंट काफी पहले से तय कर लिए जाते हैं और ये राज्य में क्रिकेट के विकास तंत्र का एक अहम हिस्सा हैं।

राज्य सरकार ने प्रोडक्शन हाउस 'लाइट रेज' को आजाद मैदान में 5000 वर्ग गज सरकारी जमीन का छह घंटे तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके लिए 40000 रुपये का किराया और 40000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट (सुरक्षा राशि) ली गई है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, खेल उप निदेशक नवनाथ फर्टाडे ने कहा एक सरकारी प्रस्ताव (ज़क्र) के तहत विभाग को यह अधिकार है कि वह साल में 30 दिनों तक आजाद मैदान को खेल-कूद के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित कर सकता है।

क्या बोले निर्माता

'प्रलय' के निर्माता हंसल मेहता ने बताया कि शूटिंग शुरू करने से पहले उनकी प्रोडक्शन टीम ने संबंधित अधिकारियों से सभी जरूरी अनुमतियां ले ली थीं।

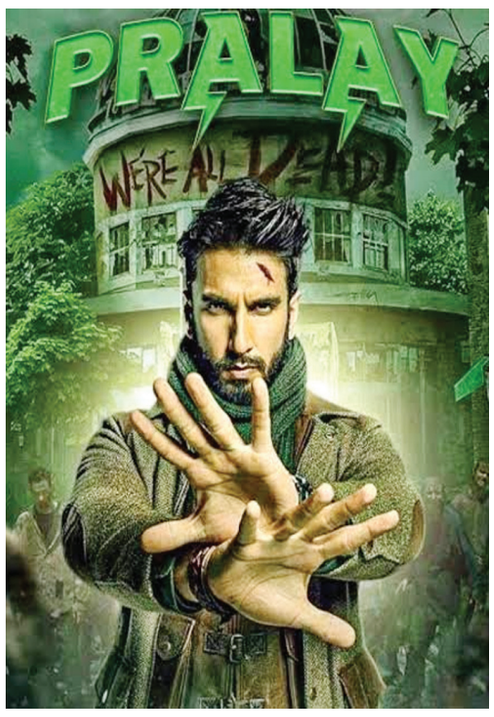





बॉलीवुड एक्ट्रेस राइमा सेन ने महल छोड़कर चुनी फिल्मों की दुनिया

फिल्म दुनिया में अपनी पहचान बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब कोई शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद अभिनय की राह चुनता है, तो उनकी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अभिनेत्री राइमा सेन भी शाही परिवार से आती हैं, जिनका नाता राजघराने से रहा है। शाही परिवार से पली-बढ़ी राइमा ने ग्लैमर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया। 7 नवंबर 1979 को मुंबई में जन्मी अभिनेत्री राइमा सेन शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भरत देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य हैं। उनकी दादी, इला देवी, कूच बिहार की राजकुमारी थीं और उनकी छोटी बहन गायत्री देवी जयपुर की महारानी थीं। वहीं, अभिनेत्री की मां मुनमुन सेन जानी-मानी अभिनेत्री हैं और उनकी नानी सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की महान नायिका (महानायिका) मानी जाती थीं। घर में नानी और मां के अभिनय से जुड़े होने के कारण उन्हें अभिनय की दुनिया विरासत में मिली। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म 'गॉडमदर' से की थी, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। इसके बाद वे फिल्म 'दमन' में नजर आईं। बंगाली सिनेमा में रितुपर्णो घोष की फिल्म 'चोखेर बाली' में ऐश्वर्या राय के साथ उनके काम की बहुत सराहना हुई थी। इसके अलावा वह प्रमुख बंगाली फिल्मों 'बैशे श्राबोन', 'नौका डूबी', 'हृद मझारे' और 'माछ मिष्टी एंड मोर' में नजर आई थीं। उन्होंने साल 2005 में विद्या बालन के साथ फिल्म 'परिणीता' में काम किया, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में भी बड़ी पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान और विद्या बालन के साथ काम किया था। साल 2011 में अभिनेत्री 'बैशे श्राबोन' में नजर आई थीं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ-साथ राइमा सेन के काम की भी सराहना हुई थी। उन्होंने 'द जापानी वाइफ', 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड', 'द वैक्सीन वॉर' और 'मिस्ट्री चेज़' जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया है। उनकी प्रमुख वेब सीरीज में 'हैलो!', 'द लास्ट ऑवर' और 'माई' शामिल हैं।



आईपीएस अफसर किरदार निभाने के लिए खुद से ज्यादा निर्देशक को भरोसा था

निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की आगामी पैन-इंडियन एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'ओमः चैप्टर 1- उधिराम : द ब्लड वुड' में अभिनेत्री साई पल्लवी आईपीएस अफसर के किरदार में नजर आएंगी। अभिनेत्री का कहना है कि इस किरदार को निभाने के लिए उनसे ज्यादा निर्देशक को उन पर ज्यादा भरोसा था। शुक्रवार को साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए फिल्म के ग्रैंड ऑडियो लॉन्च इवेंट में हिस्सा लेते हुए साई पल्लवी ने कहा, 'राजकुमार पेरियासामी कमाल के निर्देशक हैं। मैंने उन्हें पिछली फिल्म में ही कह दिया था कि मैं उनकी अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूं लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियस लिया और यह फिल्म बनाई। मेरे पुलिसवाले रोल पर उन्हें मुझसे भी ज्यादा भरोसा था। स्टंट सीक्वेंस पर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया, उनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। राजकुमार सर ने इस किरदार को कई परतों के साथ लिखा है। वो हर एक्ट्रेस के ड्रीम डायरेक्टर हैं, जिस तरह से वो महिलाओं के किरदार लिखते हैं, वो कमाल है।' अभिनेत्री ने बताया कि उनकी पिछली फिल्म 'अमरन' में उनके किरदार को पूरे समय 'ममूटी' कहकर पुकारा जाता था और अब उन्हें उसी मलयालम सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, 'पिछली फिल्म में ममूटी-ममूटी कहकर अब ममूटी सर के साथ। पता नहीं क्या मैंने इसे मैनिफेस्ट कर लिया था।' फिल्म 'ओमः चैप्टर 1 - उधिराम : द ब्लड वुड' में अभिनेत्री साई पल्लवी एक कड़क और शक्तिशाली पुलिस अधिकारी नित्या रेड्डी (आईपीएस/सीबीआई अधिकारी) की भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। नित्या रेड्डी इसी तस्करी के नेटवर्क की जांच करने के लिए 'ऑपरेशन ओम' के तहत मैदान में उतरती हैं। उनकी जांच के पीछे एक व्यक्तिगत नुकसान की वजह जुड़ी है, जो उन्हें न्याय पाने के लिए प्रेरित करती है।

फिल्म 'लड़ाकू' से बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं कार्तिक आर्यन

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कार्तिक आर्यन और कबीर खान की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। दोनों की अगली फिल्म का नाम और रिलीज डेट सामने आ गई है। बता दें कि फिल्म का नाम 'लड़ाकू' है। मेकर्स ने इसे एक ऐसी फिल्म बताया है, जो दर्शकों को भावुक करने के साथ प्रेरित भी करेगी। खास बात यह है कि इस फिल्म के साथ कार्तिक आर्यन बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं।

बुधवार को बिरला स्टूडियोज ने फिल्म 'लड़ाकू' की रिलीज डेट का ऐलान किया। यह फिल्म 18 जून, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को बिरला स्टूडियोज और कबीर खान एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं, डोपामिन स्टूडियोज के जरिए कार्तिक आर्यन भी बतौर निर्माता इस फिल्म से जुड़ रहे हैं। मेकर्स के मुताबिक, 'लड़ाकू' एक सच्ची घटना पर आधारित असाधारण कहानी है, जिसमें महत्वाकांक्षा, हिम्मत और उम्मीद की झलक देखने को मिलेगी। इसे एक फैमिली एंटरटेनर बताया जा रहा है। फिलहाल फिल्म की कहानी, बाकी कलाकारों और क्रू से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।

'चंदू चैंपियन' में कर चुके हैं साथ काम

बता दें कि कार्तिक आर्यन और कबीर खान इससे पहले साल 2024 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' में साथ काम कर चुके हैं। यह फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म को क्रिटिक्स की खूब तारीफ मिली थी। कई लोगों ने इसे कार्तिक के करियर की अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस भी बताया था। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को खास सफलता नहीं मिली। करीब 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में लगभग 88 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। बाद में ओटीटी पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह फैंस की पसंदीदा फिल्मों में शामिल हो गई।

'बेवफा सनम' में नील नितिन मुकेश के साथ काम कर बोलीं कशिका कपूर

अभिनेत्री कशिका कपूर सॉन्ग 'बेवफा से' में नील नितिन मुकेश के साथ नजर आ रही हैं। उनके साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कशिका ने बताया कि वह कभी आपको यह एहसास नहीं होने देते कि आप किसी सीनियर अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं। अभिनेत्री कशिका कपूर ने बातचीत में अभिनेता नील नितिन मुकेश के साथ काम करने के अनुभव को मजेदार बताते हुए कहा, 'किसी सीनियर एक्टर से आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नील को इंडस्ट्री में कई साल काम करने का काफी अनुभव है। यह एक शानदार सीखने वाला अनुभव था और हमने खूब मस्ती भी की। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूं।' अभिनेत्री ने बताया कि शूट होने से पहले उन्हें गाने के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई गई थीं। उन्होंने कहा, 'नील नितिन मुकेश के आने से कुछ महीने पहले ही यह प्रोजेक्ट लॉक हो गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह गाना सच में बनेगा या इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आखिर में जब नील नितिन मुकेश फाइनल हुए तो मेकर्स ने गाने की धुन को देखते हुए इसमें एक डांस नंबर जोड़ने का फैसला किया। हमने रिहर्सल शुरू की और सब कुछ काफी अच्छा हुआ। तभी कहानी भी तैयार हुई। कशिका कपूर ने बताया, 'मुझे उम्मीद थी कि गाना लोगों को पसंद आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कमाल का है। मुझे लगता है जेन जी इस कहानी से इसलिए जुड़ रहे है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ऐसी चीजें काफी आम होती जा रही हैं। ओपन रिलेशनशिप और धोखा जैसी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं और शायद यही वजह है कि दर्शक इस गाने से इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'लोगों ने हमारे गाने को खुले दिल से अपनाया है और इतना प्यार दिया है। मैं इस रिस्पॉन्स के लिए बहुत आभारी हूं।



अभिनेता के तौर पर अलग तरह की दुनिया और किरदार करना हमेशा मजेदार होता है

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने अपनी आगामी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' के रिलीज से पहले कहा है कि किसी फिल्म या किरदार का चुनाव करते समय वह अपने अंदर के बच्चे की बात सुनती हैं। फिल्म के प्रचार के दौरान मुंबई में अपने सह-कलाकार पंकज त्रिपाठी के साथ बातचीत में अदिति ने कहा कि उन्हें इस फिल्म की कहानी बेहद प्यारी लगी। उन्होंने कहा, मुझे यह एक साधारण जिंदगी से जुड़ी कहानी वाली फिल्म लगी। इसके साथ जुड़े लोग भी ऐसे थे, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे आम तौर पर नहीं मिलता। यही सब बातें थीं, जिन्होंने मुझे यह फिल्म करने के लिए प्रेरित किया। अदिति ने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर अलग तरह की दुनिया और किरदार में काम करना हमेशा मजेदार होता है। उन्होंने कहा, 'इस फिल्म में एक हल्कापन था, जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं बस इसे करना चाहती थी। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे भीतर एक उत्साह और सहज भावना थी। मैं अपने अंदर के बच्चे की सुनती हूं। अगर किसी चीज को लेकर मैं उत्साहित होती हूं, तो मेरे लिए उस सफर का महत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं होता।' उन्होंने कहा, 'अगर यात्रा मजेदार हो, उसमें रोमांच हो, सीखने का अवसर हो और अच्छे लोग साथ हों, तो वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार वही अनुभव आपके साथ हमेशा रहता है।'



जनजातीय विकास की दिशा में बढ़ते कदम



उमेश चतुर्वेदी

जनजातीय गौरव दिवस के बहाने यह पड़ताल जरूरी है कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके गांवों और घरों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की गति पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की योजनाओं की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अगर कामयाब हुआ तो इसलिए कि उसमें देश के हर वर्ग और तबके ने हिस्सा लिया था। जिस जनजातीय समुदाय को लेकर धारणा रही है कि वह मुख्यधारा से दूर रहा है, उस समुदाय ने भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ना सिर्फ गहन भागीदारी की, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने में योगदान भी दिया। इसी समुदाय के थे बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा तक प्राप्त है। उनकी अगुआई में जनजातीय समुदाय ने स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय की भागीदारी और उनके योगदान की स्मृति में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस लिहाज से इस बार छठवीं बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस के बहाने यह पड़ताल जरूरी है कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके गांवों और घरों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की गति पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की योजनाओं की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसकी वजह भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज संभालने के बाद से ही जनजातीय विकास के लिए कई योजनाओं को ना सिर्फ शुरू कर रखा है, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सन् 1875 में झारखंड के रांची जिले के उलीहातू में हुआ था। बिरसा सिर्फ स्वाधीनता सेनानी ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों, भूमि छीने जाने, बेगारी आदि के विरुद्ध जनजातीय समुदायों को संगठित कर उलगुलान किया था। उलगुलान का अर्थ होता है, महान विद्रोह। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी जिंदगी स्वाधीनता के नाम होम कर दी। इन्हीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पिछले साल मनाई गई थी। बहरहाल हमें यह भी याद रखना होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय समाज के दूसरी हस्तियों मसलन, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदा



सिंह, वीर गुंडाधुर, ठाकुर रामप्रसाद पोर्ते, रानी दुर्गावती आदि को भी याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिवस को ना सिर्फ याद करती रही है, बल्कि उनकी याद में कई सारे विकास कार्यक्रमों को भी आगे लेकर आई है। इसमें सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन योजना। इसे 15 नवंबर 2023 को तीन वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना के दायरे में देश के सभी आदिवासी समुदाय आते हैं। इसे स्वाधीन भारत के इतिहास की जनजातियों पर केंद्रित यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस योजना में जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़े नौ मंत्रालयों 11 महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इसके तहत आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर आदि की उपलब्धता तय की जा रही है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित पांच विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों मसलन, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर की बसाहटों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 1545 ग्राम एवं 2365 छोटी बस्तियां शामिल हैं। इसके तहत राज्यम अब तक स्वीकृत 34,691 पक्के आवासों में से करीब 69 प्रतिशत यानी 24,218 आवास बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 2,901 किलोमीटर सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी करीब 1,833 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ ने राज्य के 7,349 जनजातीय परिवारों के घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। राज्य में जनजातीय समुदायों के लिए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और वे सारे कार्यरत हैं। इनमें से 187 के पास अपने भवन भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1425 जनजातीय गांवों के लिए पेयजल योजना मंजूर की गई थी, जिनमें से 510 में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इसी तरह इन इलाकों के लिए 57 मेडिकल वैन संचालित किए जा रहे हैं। जिनके जरिए आदिवासियों के घरों तक अस्पताल पहुंच रहा है और छोटे रोगों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जा रहा है। राज्य के स्वीकृत सभी 16 वन अनुसंधान केंद्र भी पूरी तक काम कर रहे है। राज्य में जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए स्वीकृत चालीस छात्रावासों में से 29 में छात्र रहने लगे हैं, जिससे उन्हें सहूलियत हो रही है। राज्य में जनजातीय विकास के लिए 1719 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 849 पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं, जहां आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जनजातीय समुदाय के विकास की दिशा में एक और बड़ी योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान भी है। जिसे दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। हजारीबाग से शुरू इस योजना के तहत 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में फैले 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांवों को शामिल किया गया है। जाहिर है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों के 6691 गांव शामिल हैं। इसमें 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं और गतिविधियां जैसे पक्के घर, जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, हॉस्टल, पोषण वाटिकाएं, एलपीजी कनेक्शन, भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल पहल, सतत कृषि को बढ़ावा, मछली पालन सहायता, वन अधिकार पत्र धारकों हेतु पशुधन पालन, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, क्लस्टर, ट्राइबल होमस्टे आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास के लिए राज्य में वन अधिकार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए उपयोजना बजट व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में साल 2023-24 में जहां 21,492 करोड़ 34 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, वहीं साल 2026-27 के लिए 42,165 करोड़ 95 लाख 95 हजार रुपये। स्वीकृत किए गए थे। जाहिर है कि इन योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ जहां जनजातीय समुदायों के गौरव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस समुदाय के लोगों को यह संदेश देने की कवायद में जुटा हुआ है कि वे भी देश के वैसे ही नागरिक हैं, जैसे दूसरे लोग हैं।

संपादकीय

चुभती महंगाई

बीते माह देश में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल से महंगाई दो साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह स्पष्ट है कि देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति महंगाई को काबू में रखने में विफल रही है। चिंता की बात है यह महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित छह फीसदी की तय अधिकतम सीमा को पार कर गई है। इसके साथ ही दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति निर्धारण करने वाली कमेटी की बैठक में नीतिगत ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की आशंका बलवती हुई है। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक का इजाफा किया था। पिछले एक साल से लगातार बढ़ रही खुदरा महंगाई का दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना बताता है कि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई है। जाहिर है इसका दबाव घरेलू बजट पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते माह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत तक जा पहुंची है। जिसके चलते अगले माह की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट बढ़ने की संभावना फिर प्रबल हो गई है। आशंका है कि इससे उपभोक्ताओं के घर व वाहन आदि के लोन की मासिक किस्ते लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों, जिनकी मूल्य सूचकांक निर्धारण में चालीस फीसदी की हिस्सेदारी होती है, की महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। देश में सब्जियां, दालें और किराना का अन्य सामान महंगा हो गया है। वहीं अनाज, तिलहन और चीनी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है। यहां उल्लेखनीय है कि अक्तूबर माह में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई है। यही वजह है कि लोगों को आशंका है कि उनके लिये आने वाली सर्दियों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

यूं तो महंगाई आजकल, वैश्विक उथल-पुथल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण विश्वव्यापी समस्या हो गई है। खासकर रूस व यूक्रेन तथा खाड़ी में जारी संघर्ष के चलते पेट्रोलियम पदार्थों व उनसे बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन भारत में बढ़ती महंगाई के कारणों में मौसम की संवेदनशीलता व मुद्रास्फीति भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि देश में घरेलू महंगाई दर लगातार बारहवें महीने बढ़ी है। खाने-पीने की चीजों के अलावा, इसमें परिवहन से जुड़े खर्च, कपड़े,आवास और भोजन से जुड़ी सेवाओं का भी योगदान रहा है। हालांकि, खाड़ी संघर्ष में स्थितियां सामान्य होने की ओर बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। यद्यपि, सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को इसका लाभ न मिला हो,लेकिन दामों में कमी अपरोक्ष रूप से कुछ राहत देने वाली जरूर है। इसके बावजूद महंगाई का दबाव बना रहेगा। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य महंगाई दर अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, जो कमजोर और असमान मानसून के असर को दर्शाती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा ही दिया है।

चिंतन-मनन

सफलता का मार्ग

संग्रह की वृत्ति बहिमरुखता का लक्षण है। साधक क्षणजीवी होता है। अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता वह करता है जो आत्मस्थ नहीं होता। वर्तमान में जीना आत्मस्थता का प्रतीक है। एक साधक कल की जरूरत को ध्यान में रखकर संग्रह नहीं करता, पर एक व्यवसायी सात पीढ़ियों के लिए पूरी व्यवस्था जुटाने में संलग्न रहता है। यह बात सही है कि साधक अशरीरी नहीं होता, शरीर की अपेक्षाओं को वह गौण नहीं कर सकता; पर दैहिक अपेक्षाओं को लेकर वह मूढ़ नहीं हो सकता। उसका विवेक जागृत रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखता है।

कभी-कभी साधक के जीवन में भी स्वच्छंदता, सुविधावाद और संग्रहवृत्ति जाग सकती है। प्रश्न उठता है कि इन वृत्तियों का उत्स क्या है? कौन-सी अभिप्रेरणा इन्हें उभरने का अवसर देती है? मेरे अभिमत से इन तीन संस्कारों का उद्भव तीन आकारों से होता है। वे तीन आकार हैं- अहं, अश्रम और असंतोष। स्वच्छंदता की मनोवृत्ति वहीं सक्रिय होती है, जहां अहंकार का नाग फन उठाए रखता है। अहंवादी व्यक्ति स्वयं को सब कुछ समझता है। उसे अपने सामने अन्य सभी लोग बौने दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में वह न तो किसी से मार्गदर्शन ले सकता है और न किसी के नियंत्रण में रह सकता है।

सुविधावाद का भाव वहां विकसित होता है जहां व्यक्ति श्रम से जी चुराता है, अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता और पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करता। अश्रम का बीज ही आगे जाकर सुविधावाद के रूप में पल्लवित होता है। इस दृष्टि से साधना के साथ श्रमशीलता की युति आवश्यक है। संग्रह वृत्ति का बीज है असंतोष। जिस व्यक्ति को पदार्थ में संतोष नहीं होता, वह संग्रह करने की बात सोचता है। जिस समय जैसा पदार्थ उपलब्ध होगा, उसी से आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी- यह विधायक चिंतन असंतोष की जड़ को काट सकता है और संग्रह की मनोवृत्ति को बदल सकता है। साधना की सफलता स्वच्छंदता, सुविधावाद और संग्रहवृत्ति में नहीं है।

फास्ट फूड और मोबाइल की गिरफ्त में बचपन, डायबिटीज का बढ़ता खतरा

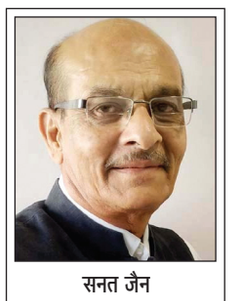

सनत जैन



भारत में डायबिटीज की बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। बच्चों और युवाओं में भी तेजी से बढ़ते मधुमेह के मामले समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। कभी जिस उम्र में बच्चे खेल के मैदानों में दौड़ते-कूदते थे, आज उसी उम्र में वे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम की दुनिया में घंटों व्यस्त रहते हैं। दूसरी ओर खानपान की बदलती आदतों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। पिछले दो-तीन दशकों में भारतीय परिवारों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। परिवारों में एक या दो बच्चे होने के कारण माता-पिता उनकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की जिद के सामने फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थ आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते हैं। धीरे-धीरे यह भोजन बच्चों की पसंद ही नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाता है। फास्ट फूड में अधिक मात्रा में नमक, चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और कैलोरी होती हैं। इनका नियमित सेवन मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।

बचपन में विकसित हुई गलत खानपान की आदत के कारण अब कम उम्र में ही शुगर की बीमारी देखने को मिल रही है। जो जीवनभर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी बड़ी समस्या शारीरिक गतिविधियों का लगातार कम होना है। पहले बच्चे स्कूल से लौटने के बाद मैदानों में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और दूसरे खेल खेलते थे। आज उनका अधिकांश समय मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम में बीत रहा है। शारीरिक श्रम, पैदल चलना, साइकिल चलाना और व्यायाम जीवनशैली से गायब होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन और फास्ट फूड दोनों बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षण और आदत का ऐसा चक्र बना रहे हैं, जिससे बाहर निकलना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। मोबाइल नहीं मिलने पर बच्चों का चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार भी अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अनियंत्रित स्क्रीन का इस्तेमाल और अस्वास्थ्यकर खानपान के दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज केवल खानपान और व्यायाम की कमी से ही नहीं होती। कभी-कभी इसके आनुवंशिक कारण, पारिवारिक इतिहास, नींद की कमी, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां भी इसके जोखिम को प्रभावित करती हैं। टाइप-1 डायबिटीज बच्चों में भी हो सकती है। जो खानपान या मोटापे से नहीं होती। इसलिए बीमारी के सभी स्वरूपों को समझना जरूरी है।

इंटरनेशनल डायबिटीज डे के इस अवसर पर यह संकल्प लेना होगा, कि बच्चों को केवल महंगे स्कूल, मोबाइल और आधुनिक सुविधाएं देना ही अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवनशैली देना भी उतना ही आवश्यक है। घर में पौष्टिक भोजन, फल, सब्जियां और पारंपरिक खानपान को प्राथमिकता मिले। फास्ट फूड को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनाने से बचें। बच्चों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। स्कूलों में खेल के मैदान, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। माता-पिता को भी बच्चों के साथ पैदल चलना, खेलना और व्यायाम करना चाहिए। जिससे बच्चों की भी आदत पड़ेगी। मां-बाप का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया में व्यस्त रखकर उनका बचपन छीन रहे हैं, या उन्हें स्वस्थ भविष्य देने की तैयारी कर रहे हैं? डायबिटीज से बचाव की शुरुआत अस्पताल से नहीं, बल्कि घर की रसोई, भोजन की थाली और खेल के मैदान से होनी चाहिए। आज की छोटी-सी सावधानी आने वाली पीढ़ी को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। उनका बेहतर करियर भी बना सकती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी सभी चीजें ठीक-ठाक रहेंगी।

भारत के आर्थिक विकास में राज्यों को बढ़ानी होगी अपनी हिस्सेदारी



प्रहलाद सबनानी

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के समस्त राज्यों को देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। विशेष रूप से उन राज्यों को, जिनकी आर्थिक विकास दर देश की औसत आर्थिक विकास दर से नीचे है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक विकास दर हासिल करना आवश्यक है।

वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। परंतु, 1980 के दशक में इन राज्यों को 'बीमारु' राज्य की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत के 10 में से 4 नागरिक इन राज्यों में निवास करते थे। साथ ही, इन राज्यों की आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी जिससे इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी।

वर्ष 2000-01 में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान 22 प्रतिशत था जो वर्ष 2034-24 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया। पिछले, लगभग 25 वर्षों के दौरान देश के इन चारों बड़े राज्यों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग उसी स्तर पर बना रहा है, जो एक चिन्तनीय विषय होना चाहिए। यदि देश के सबसे बड़े राज्यों का देश के आर्थिक विकास में योगदान नहीं बढ़ेगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में किस प्रकार शामिल हो सकता है। अतः उक्त बड़े चारों राज्यों को अपने आर्थिक विकास को गति देना अब एक आवश्यक आवश्यकता बन गया है।

वर्ष 2024-25 के प्रति व्यक्ति आय (GSDP) के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो ध्यान में आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर 234,859 रुपए प्रतिवर्ष था। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 76,000 रुपए प्रतिवर्ष थी, उत्तर प्रदेश में यह 126,304 रुपए थी, मध्य प्रदेश में 170,320 रुपए थी एवं राजस्थान में 206,440 रुपए थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुणा अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। पूरे भारत में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत है जबकि, राजस्थान में 7.7 प्रतिशत एवं बिहार में 7.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से रोजगार पाने के उद्देश्य से नागरिकों का देश के अन्य प्रदेशों में पलायन 37 प्रतिशत है। अर्थात, पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाले नागरिकों के पलायन का 37 प्रतिशत हिस्सा केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश का होता है। क्योंकि, इन राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित नहीं हो रहे हैं एवं इन प्रदेशों के नागरिक मजबूरी में अन्य राज्यों को पलायन करते हैं ताकि उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त हो सके। उक्त कारणों के चलते ही, उक्त चारो राज्यों को 'बीमारु' राज्यों की संज्ञा दी गई थी। परंतु, हाल ही के समय में इन राज्यों में, विशेष रूप से, आर्थिक क्षेत्र में, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उक्त चारों राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत में कृषि के औसत योगदान की तुलना में, बहुत अधिक है। अर्थात इन राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 47 प्रतिशत है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत है। प्रदेश की अधिकतम आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है एवं अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अधिक आबादी के कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के चलते प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विकसित नहीं होने के चलते इन क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर निर्मित होते हैं एवं मजबूरी में प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या को कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ता है अथवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों को पलायन करना होता है। इसी प्रकार, राजस्थान में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, 26 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 43 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। उत्तर प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत कृषि क्षेत्र, 28 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र एवं 44 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। बिहार में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से, 18 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 57 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। जबकि, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16 से 18 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 18 से 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 62 से 64 प्रतिशत है।

हाल ही के समय में, उक्त चारों राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश, ऑटोमोबाईल उत्पादन के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित हो चुका है। इंदौर के आसपास विकसित किए गए ऑटोमोबाईल हब में 10 से अधिक चार पहिया उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं एवं 200 से अधिक ऑटो कम्पोनेंट का उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है एवं मखाना उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या को बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है। राजस्थान भी 10 वर्ष पूर्व ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या को कम करने में सफल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में आज उत्तर प्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। राजस्थान 6ठे स्थान पर, मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर एवं बिहार 14वें स्थान पर आ गए हैं।

हाल ही के समय में उक्त चारों राज्यों में आर्थिक विकास ने कुछ गति जरूर पकड़ी है परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन चारों राज्यों की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य तुलनात्मक रूप से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग जगत के लिए मित्रवत नीतियों को बनाकर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को इन राज्यों को बढ़ावा देना होगा, ताकि इन राज्यों में कृषि के क्षेत्र पर दबाव कम हो एवं उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान न केवल सकल घरेलू उत्पाद में बल्कि रोजगार के नए अवसर निर्मित करने में भी बढ़े।

आज, उक्त चारों राज्य ÷बीमारु÷ राज्य की श्रेणी से तो बाहर निकल आए हैं, परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपने योगदान को बढ़ाने के लिए इन राज्यों को विशेष प्रयास करने होंगे। इन राज्यों के नागरिकों को आगे आने वाले कुछ वर्षों तक केवल अपने प्रदेश के आर्थिक विकास पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इन राज्यों में विभिन्न समाजों को विशेष प्रयास करते हुए, प्रदेश में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होने देना चाहिए। दरअसल, भारत आज विकास के उस चक्र में पहुंच गया है, जहां किसी भी प्रकार का आंदोलन देश के आर्थिक विकास की गति को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः समाज की सज्जन शक्ति को इस ओर विशेष ध्यान देकर समस्त समाज के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए प्रदेश में शांति स्थापित करने के प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। प्रदेश की सरकारें तो आर्थिक नीतियों को लागू करने के प्रयास कर ही रही हैं परंतु, समाज को भी संगठित होकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता है। प्रदेश का आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, अर्थात मां भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ करने की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास माना जाना चाहिए। आज उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात द्वारा अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने के भरपूर प्रयास किया जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रयास, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं बिहार राज्यों द्वारा भी किए जाने चाहिए, ताकि शीघ्र ही भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के ऊपर लाया जा सके एवं भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।

(सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर विधायक लक्ष्मण मीणा की कुशलक्षेम जानी



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर स्थित राजस्थान हॉस्पिटल पहुंचकर बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने विधायक के परिजनों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया।

आईआईटीएफ- 2026

प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का किया उद्घाटन



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 15 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शनिवार को राज्य के प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार ने राजस्थान मंडप का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राजस्थान मंडप के निदेशक हर्ष शर्मा ने रोहित कुमार को मंडप का अवलोकन करवाते हुए बताया कि इस वर्ष राजस्थान पार्टनर स्टेट है और राजस्थान मण्डप को 'विकास और विरासत' की थीम के अनुरूप तैयार किया गया है।

रोहित कुमार ने राजस्थान मण्डप के सभी स्टॉल का अवलोकन कर राजस्थानी कलाकारों और हुनरबंद कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। मंडप निदेशक ने बताया कि मेले में मण्डप को उद्योग व पर्यटन विभाग, रीको, बीआईपी, खादी, राजीविका की सहभागिता से और भी समृद्ध बनाया गया है। यहां राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल भी लगाई गई हैं।

मेले में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा लगभग एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में राजस्थान मंडप का निर्माण किया गया है। इसमें राजस्थान की औद्योगिक प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, कला, शिल्प, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं की विशिष्ट झलक देखने को मिल रही है।

21 नवंबर को होगा राजस्थान दिवस समारोह

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान इस वर्ष 21 नवंबर को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

गांव–गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की तैयारी, आशा-एएनएम को मिला विशेष प्रशिक्षण

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर 'ब' के अधीन संचालित आयुष्यान आरोग्य मंदिर के अन्तर्गत कार्यरत आशा एएनएम नर्स-कम्पाउण्डर आयुष मित्र की दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शुभारम्भ डॉ. राजेश शर्मा एवं अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर संभाग डॉ. बत्तीलाल बैरवा ने भगवान धन्वन्तरि की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।

विभाग के उपनिदेशक डॉ. मुखत्यार सिंह ने बताया शिविर में प्रतिभागियों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों पर इनके द्वारा किया जाने वाले कार्यों की योजना का आमुखीकरण, प्रकृति परीक्षण की आवश्यकता, सीबीएसी फॉर्म, लेबोरेट्री टेस्ट, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, आयुष में रेफरल सिस्टम, आयुष मेडिसिन किट, एनसीडीएस की स्क्रीनिंग, घरेलु उपचार एवं औषधीय पादपों का उपयोग, आयुष आईईसी एवं योग एवं स्वस्थ जीवनशली रिपोर्टिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि डॉ. सत्यनारायण शर्मा उप निदेशक जयपुर 'अ', डॉ. घनश्याम मीणा उप निदेशक कैम्प कार्यालय नरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट, डॉ. ऋषि तिवाड़ी, डॉ. ऋचा तिवारी, डॉ. विजय कुमार, डॉ. ज्योति यादव, डॉ. कृति शर्मा व डॉ. संतोष कुमारी एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्किल में आमजन के साथ की मॉर्निंग वॉक

बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से किया संवाद, समस्याएं सुनी एवं सुझाव भी लिए

मंदिर में दर्शन कर की प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए कामना

प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया' अभियान को बताया स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण का आधार

आवाज़ ए तसनीम





जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के जवाहर सर्किल में आमजन के साथ मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उन्होंने प्रातः भ्रमण कर रहे बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से आत्मीय मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया और विभिन्न विषयों पर संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं एवं सुझाव भी लिए। वहीं, बच्चों से उनकी शिक्षा एवं दिनचर्या की जानकारी लेते हुए स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया और उन्हें चॉकलेट भी वितरित की। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने आमजन के साथ छाछ पीकर स्वस्थ खान-पान अपनाने एवं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर 'वोकल फॉर लोकल' अभियान में भागीदारी निभाने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फिट इंडिया अभियान स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण का आधार है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी और हम अपने कार्यों को अधिक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ कर सकेंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपने आसपास गंदगी नहीं होने देने तथा कहीं भी गंदगी दिखाई देने पर प्रशासन को सूचित कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

'हर वर्ग के उत्थान एवं जनकल्याण के लिए सरकार कृतसंकल्पित'

मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार ने विगत तीन वर्षों में जनकल्याण की अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा है तथा लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने आमजन से नियमित व्यायाम, योगाभ्यास एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मॉर्निंग वॉकर्स में भी काफी उत्साह देखने को मिला एवं उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण में 71.81 प्रतिशत मतदान

चारों पंचायत समितियों एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए शांतिपूर्ण मतदान

तूंगा में सर्वाधिक 72.77 प्रतिशत तथा आंधी में 70.12 प्रतिशत मतदान

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में चतुर्थ एवं अंतिम चरण में शनिवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले की चार पंचायत समितियों–बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी में पंचायत समिति सदस्य पदों के 82 निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान में कुल 71.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जयपुर संदेश नायक ने बताया कि चारों पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 2 लाख 92 हजार 452 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

पंचायत समिति-वार प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार आंधी में कुल 91 हजार 16 मतदाताओं में से 63 हजार 817 ने मतदान किया, जो 70.12 प्रतिशत रहा। बस्सी में 1 लाख 29 हजार 159 मतदाताओं में से 93 हजार 462 ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 72.36 रहा। जमवारामगढ़ में 1 लाख 22 हजार 890 मतदाताओं में से 88 हजार 444 ने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां मतदान प्रतिशत 71.97 दर्ज किया गया। इसी प्रकार तूंगा में कुल 64 हजार 215 मतदाताओं में से 46 हजार 729 ने मतदान किया तथा यहां सर्वाधिक 72.77 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

मतदान के समयवार आंकड़ों के अनुसार प्रातः 10 बजे तक 15.25 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 34.56 प्रतिशत, अपराह्न 3 बजे तक 51.28 प्रतिशत तथा सायं 6 बजे तक 70.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अंतिम आंकड़ों के अनुसार मतदान प्रतिशत 71.81 रहा।

उल्लेखनीय है कि चतुर्थ चरण के तहत बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी पंचायत समितियों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए 15 नवंबर को प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नामांकन होंगे तथा 16 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच का चुनाव 17 नवंबर को होगा। सभी चरणों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिनभर विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

चतुर्थ चरण में बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए हुआ मतदान

मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जयपुर जिले में शनिवार को चतुर्थ चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जयपुर संदेश नायक ने दिनभर बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी पंचायत समितियों के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने खोखावाला, भांगड़ कला, सहित चारों पंचायत समितियों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। वहां तैनात मतदान कार्मिकों से निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं, मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना का निरीक्षण किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने चतुर्थ चरण के मतदान को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने में सहयोग देने के लिए बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी पंचायत समितियों के समस्त मतदाताओं, आमजन, जनप्रतिनिधियों एवं निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

उल्लेखनीय है कि चतुर्थ चरण के तहत इन चारों पंचायत समितियों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान होगा तथा उपसरपंच का चुनाव 17 नवंबर को होगा।

बाल दिवस पर बच्चों ने सड़क सुरक्षा रैली निकालकर दिया यातायात नियमों की पालना का संदेश

हेलमेट, सीट बेल्ट एवं वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने के प्रति किया जागरूक

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। बाल दिवस एवं 15 नवंबर को राज्य सड़क सुरक्षा दिवस तथा विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मरण दिवस के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस जयपुर और एक निजी विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भगवान दास रोड एवं आसपास सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न संदेशों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों की पालना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (प्रशासन एवं यातायात) प्रदीप मोहन, पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल दिवस के अवसर पर बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को स्मरण कर आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना रहा। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। बच्चों ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने अपने संदेशों के माध्यम से बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है तथा थोड़ी सी सावधानी कई अनमोल जीवन बचा सकती है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात दक्षिण श्रीमती सुनीता मीणा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। उन्होंने आमजन से यातायात नियमों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों की पालना कर स्वयं के साथ दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनजातीय गौरव दिवस पर शुभकामनाएं

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर) की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की। यह पहल जनजातीय समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान और गौरवशाली विरासत का सच्चा सम्मान है।

उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने पूरे देश में जनक्रांति की लौ जलाई। उन्होंने समाज सुधारक के रूप में जनजातीय समाज को नशा एवं जातीय संघर्ष जैसी बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज ने विश्व को जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाया है। राज्य सरकार इन परम्पराओं को संजोने के साथ ही जनजाति कल्याण के लिए कृत-संकल्पित है।

ढेरों फायदे हैं गुड़ की चाय के



चीनी की चाय के बजाय गुड़ की चाय पीने से न सिर्फ गर्माहट मिलेगी करती है बल्कि हमें ताजगी और उर्जा से भर देगी। पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है।

इम्यूनिटी बढ़ाती है

गुड़ में कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। गुड़ की चाय नियमित रूप से पीने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है जो कि किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने की कुंजी होती है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लडने में मदद करती है। जब हमारा शरीर पर्याप्त इम्यूनिटी के साथ लैस होता है, तो वह वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमणों को फैलने से रोकने में सक्षम हो जाता है।

एनीमिया में आराम

गुड़ एक ऐसा प्राकृतिक आहार है जिसमें आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। रोजाना गुड़ का सेवन करने से आयरन की कमी पूरी होती है जिससे एनीमिया में राहत मिलती है। गुड़ को चाय पीने से एनीमिया से आराम मिल सकती है।

गर्भावस्था में फायदेमंद

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को गुड़ की चाय पीने से कमजोरी नहीं होती। गुड़ में कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुड़ की चाय गर्भावस्था में कमजोरी को कम करती है और मां और बच्चे दोनों के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को रोजाना गुड़ की चाय पीनी चाहिए।

ठंड से बचाती है

सर्दियों में लगातार गुड़ की चाय पीने से ठंड व बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती हैं. इसलिए सर्दियों में लगातार गुड़ की चाय पीना बहुत ही फायदेमंद होता है।

प्रोटीन का पावरहाउस है ये सब्जी

बहुत से लोग अंडे से प्रोटीन की जरूरत को पूरी करते हैं लेकिन रोजाना खाई जाने वाली कुछ सब्जियों में भी इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। ऐसी ही एक सब्जी ब्रोकोली है, जो गोभी की तरह दिखती है लेकिन प्रोटीन के मामले में अंडे से कम नहीं है। शाकाहारी लोग इसके सेवन से प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अंडा खाने से शरीर को करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि 100 ग्राम ब्रोकली में करीब 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसका मतलब ब्रोकली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अंडा न खाने वालों के लिए ये बेहतर ऑप्शन है।

ब्रोकोली के क्या-क्या फायदे

1. वजन कम करने में मददगार

ब्रोकली में अंडे के मुकाबिल कम कैलोरी पाया जाता है। इसमें 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, जो वजन कम करने में मददगार होता है। इसे खाने से वजन कम होता है और मोटापा भी बढने नहीं पाता है।

2. कैंसर का खतरा कम

ब्रोकोली एक तरह की क्रुसिफेरस सब्जी होती है, जिसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी कैंसर का कारण बनने वाली सेल्स को डैमेज होने से रोकने का काम करती हैं। इससे कैंसर का खतरा कम होता है।

3. हड्डियों को मिलती है मजबूती

कैल्शियम और कोलेजन हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ब्रोकली में दोनों ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इस सब्जी में विटामिन च्च भी पाया जाता है। जिसके नियमित सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस रोकने में मदद मिल सकती है।

4. इम्यून सिस्टम बनेगा मजबूत

ब्रोकोली में विटामिन सी अच्छी मात्रा



पाई जाती है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। इसके सेवन से सर्दी के मौसम में कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं।



सर्दियों में स्वास्थ्य के अच्छा क्या है- फलों का जूस या फल !

फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है या फलों का जूस पीना लाभदायक रहता है। इन दोनों में से आपको क्या चुनना चाहिए? फल स्वादिष्ट, ताजा और विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आप उन्हें सीधे खा सकते हैं या जूस निकालकर भी पी सकते हैं। फलों को मिक्स करके भी पिया जा सकता है। चाहे वह नींबू के रस के साथ फलों की चाट हो या थोड़े से सेंधा नमक के साथ एक गिलास मिक्स फलों का रस, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो आपको किसे चुनना चाहिए? आज इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि दोनों में आपके शरीर के लिए क्या बेस्ट है।

साबुत फल खाने के फायदे

पूरे फल खाने से आपके शरीर को ढेर सारा फाइबर मिलता है, जो पाचन में सुधार और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ताजे फलों को खाने से भी आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट और फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। फल खाने से मोटापे और पुरानी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। फलों और सब्जियों को खाने से शरीर को भरपूर आहार मिलता है। साथ ही फलों को खाने को वजन कम करने में भी मदद मिलती है। फलों में कैलोरी कम होती है और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में सेवन किए बिना आपको जल्दी से फ्रेश कर देती है। फल जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं उनमें जामुन, सेब, नाशपाती, खट्टे फल और अंगूर शामिल हैं।

फलों के रस के फायदे और नुकसान

फलों का रस एक या एक से अधिक फलों को मिक्स करके बनाया जाता है। यह फलों का सेवन करने का एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि, जूस में पूरे फल में पाए जाने वाले फाइबर की कमी होती है और पूरे फल के सभी पोषक तत्वों और एंटीऑक्सिडेंट को बरकरार नहीं रख पाता है। यह चीनी और कैलोरी में भी उच्च हो सकता है, खासकर यदि आप पैकेज्ड जूस पी रहे हैं।

फिटकरी और नीम की पत्तियों को मिलाकर स्किन पर लगाने से क्या होता है?



स्किन केयर में फिटकरी और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। फिटकरी में एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, जबकि नीम में एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों को कभी साथ में इस्तेमाल किया है? कॉन्टेंट क्रिएटर पूनम देवनानी ने अपने यू ट्यूब पर वीडियो शेयर कर यह बताया है कि आप इनका इस्तेमाल एक साथ कैसे कर सकते हैं और इसके फायदे। तो आइए जानते हैं फिटकरी और नीम की पत्तियों को मिलाकर लगाने के फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका।

फिटकरी और नीम की पत्तियों को स्किन पर लगाने के फायदे

अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे और एक्ने की परेशानी है तो इस कंट्रोल करने में नीम बेहद फायदेमंद है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। वहीं, फिटकरी का एंटी-सेप्टिक गुण इंफेक्शन को रोकता है। अगर आपको अपनी स्किन को टाइट करना है तो इसमें फिटकरी बेहद फायदेमंद है। इसमें एक प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट है जो खुले पोर्स को सिकोड़ती है और स्किन को टाइट रखती है।?

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले नीम की पत्तियों के साथ एक खीरा लें और उसे कट करें। अब इन दोनों को अच्छी तरह से कददूसकर कर लें. जब ये एकदम अच्छी तरह से खुन जाए तब इसे एक कॉटन के कपड़े में निकालें और इसक जूस अच्छी तरह से छान लें. अब एक सिलबट्टे पर यह जूस गिराएं और उसके ऊपर फिटकरी को रगड़े। जब फिटकरी अच्छी तरह से इसमें मिल जाए तब इसे एक बॉयल में लेकर अपनी स्किन के दाग धब्बों वाली जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। इसके बाद चेहरे को सादे या गुनगुने पानी से धो लें

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

संवेदनशील त्वचा, एक्जिमा या एलर्जी की समस्या वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। अगर चेहरे पर लगातार मुंहासे, दर्दनाक गांठें या दाग पड़ रहे हैं, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं

डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स केवल आम जानकारी के लिए हैं। सेहत से जुड़े किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने अथवा अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

घर पर बासी बचे चावल से बनाएं नमकीन, सुबह चाय के साथ खाने में आ जाएगा स्वाद, नोट करें विधि

अगर आप सुबह की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाना पसंद करते हैं, तो बासी बचे चावल से तैयार होने वाली यह नमकीन रेसिपी जरूर ट्राई करें। अक्सर घरों में रात के पके चावल बच जाते हैं और अगले दिन समझ नहीं आता कि उनका क्या किया जाए। ऐसे में आप इन चावलों से झटपट स्वादिष्ट नमकीन तैयार कर सकते हैं। इसमें सेव, बूंदी और मूंगफली का कुरकुरापन और मसालों का चटपटा स्वाद मिलेगा। इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए जानते हैं बचे हुए चावल से नमकीन बनाने की सामग्री और आसान विधि।

बासी बचे चावल से नमकीन बनाने के लिये सामग्री

एक कप चावल, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच ऑरगनों, आधा कप सेव नमकीन, आधा कप बूंदी नमकीन, आधा मूंगफली

बासी बचे चावल से नमकीन बनाने की विधि

पहला स्टेप : बासी बचे चावल से नमकीन बनाने के लिए, सबसे पहले चावल को अच्छी तरह अलग कर दें। अब उसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच ऑरगैनो डालें और सब आपस में अच्छी तरह से नमक मिलाएं।

दूसरा स्टेप : अब इसे अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सूखा दें। दो तीन बाद, जब चावल अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे तेल में अच्छी तरह से तल लें। इसे तब तक टलना है जब तक यह ब्राउन न हो जाएं।

तीसरा स्टेप : अब एक बड़े बर्तन में चावल को निकालकर, उसमें आधा कप सेव नमकीन, आधा कप बूंदी नमकीन, आधा कप भुनी हुई मूंगफली आपस में अच्छी तरह से डालकर मिलाएं। अब इसमें करी पता का तड़का दे दें। तो इस तरह का आपका चावल का नमकीन बनकर तैयार है।



सुपरफूड है अलसी

कम होगा हार्ट अटैक का खतरा

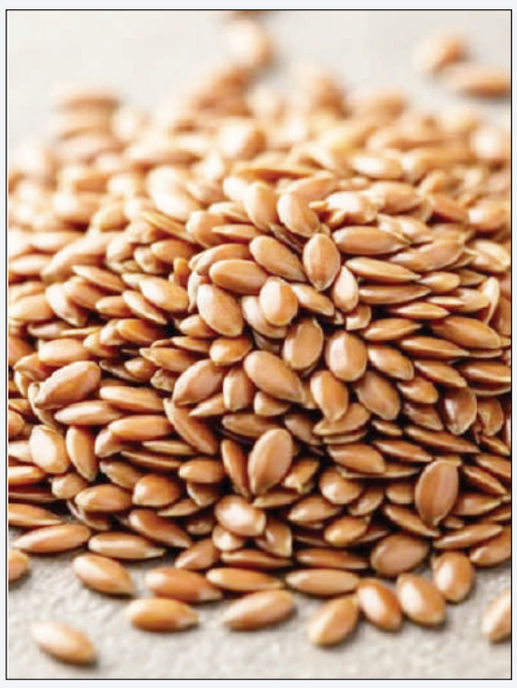

ठंड में अलसी खाने से शरीर गर्म रहता है और इम्यूनिटी मजबूत बनती है। अलसी खाने से हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। अलसी के फायदे इतने हैं कि गिनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके सेवन से बाल और त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती है। असली के बीजों में पोषक तत्वों का भंडार है।

अलसी खाने के फायदे

गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाले

अलसी के बीज खाने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है। इससे नसों की ब्लॉकेज को खोलने में मदद मिलती है। अलसी का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट को हेल्दी रखता है।

डायबिटीज में फायदेमंद

फाइबर से भरपूर अलसी में हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जिससे बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अलसी में भरपूर एंटी डायबिटीक तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन के लेवल को अच्छा रखते हैं। डायबिटीज के मरीज भुनी हुई अलसी खा सकते हैं।

कैंसर के खतरे को करे कम

अलसी खाने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। असली में एंटीऑक्सीडेंटस और एस्ट्रोजन तत्व होते हैं जो शरीर में कैंसर सेल्स को बनने से रोकते है। अलसीख खाने से कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

वजन घटाने में असरदार

अलसी के बीज खाने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है। इन्हें खाने से काफी देर तक पेट भरा रहता है। भूख कम लगती है और आप ज्यादा खाने से बचते हैं। इस तरह फाइबर से भरपूर अलसी मोटापे और जमा चर्बी को धीरे-धीरे कम कर देती है।

इन लोगों के लिए खतरनाक है मेथी का ज्यादा सेवन



भूलकर भी न खाएं

जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए मेथी के बीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जानिए मेथी के ज्यादा सेवन से किस तरह का नुकसान हो सकता है।

शुगर लेवल कम करे

शुगर के मरीजों को मेथी खाने की सलाह दी जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं मेथी का ज्यादा सेवन भी डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है। दरअसल, इसके ज्याद सेवन से ब्लड शुगर काफी नीचे जा सकता है जो शुगर के मरीजों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है।

हाई ब्लड प्रेशर

मेथी की पत्तियों में सोडियम की मात्रा कम होती है। लो सोडियम हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने पर मेथी के पत्तों के सेवन से बचना चाहिए।

सांस की बीमारी

अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो मेथी का सेवन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मेथी की तासीर गर्म होती हैं ऐसे में ये सांस से जुड़ी परेशानियों की वजह बन जाता है।

गर्भवती महिलाएं

गर्भवती महिलाओं को भी ज्यादा मेथी का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इसके ज्यादा सेवन से ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। साथ ही जो माएं बच्चों को फीड कराती हैं, उनको भी मेथी का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि ज्यादा मेथी के सेवन से फीड करने वाले बच्चों को दस्त की परेशानी हो सकती है।

पेट से जुड़ी समस्या

मेथी का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी परेशानियों गैस और अपच का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सेवन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें।

एलर्जी होने पर

अगर आपको स्किन एलर्जी की समस्या है तो आप भूलकर भी मिथिआ का सेवन न करें। मेथी के बीज के सेवन से एलर्जी फैल सकती है जिससे आपको त्वचा पर जलन, रैशेज हो सकती है।

50000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

आनंद विहार स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़

नईदिल्ली, एजेंसी। छठ महापर्व पर घर जाने वालों भीड़ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में सफर करने के लिए बड़ी संख्या में यात्री यहां पहुंचे।

बुधवार को रेलवे स्टेशन से 50 हजार से अधिक यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण रेलवे प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया का सहारा लेना पड़ा।



उधर, बस अड्डे पर भी खासी भीड़ देखी गई। जो यात्री ट्रेन से नहीं जा सके वे बसों के ब्रेक जर्नी कर अपने घरों के लिए रवाना हुए। शुक्रवार से शुरू हो रहे छठ महापर्व के चलते गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग घर जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। पूर्वांचल और बिहार जाने वाली बीस ट्रेनों के अलावा सात विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया गया था। यात्री सुमित साहू ने बताया कि छठ पर परिवार के साथ बिहार जाना है। भीड़ इतनी अधिक है कि बच्चों और सामान को संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रेन का इंतजार भी काफी देर तक करना पड़ा। विशेष झा ने बताया कि त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दी है। भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म तक पहुंचने और ट्रेन में सवार होने में परेशानी हुई।

रेलवे स्टेशन के साथ आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डे पर भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा। प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या और बनारस जाने वाली बसों में सवार होने के लिए लोग इंतजार करते रहे। परिवार और सामान के साथ यात्री जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे।

प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़

इसके लिए सुबह से ही लोग स्टेशन पहुंचने लगे। टिकट लेने के बाद प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर उन्हें होल्डिंग एरिया में रोका गया। प्लेटफार्म पर जगह बनने और ट्रेन आने के अनुसार यात्रियों को आगे जाने दिया गया इसके बावजूद यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सिर पर बैग और हाथों में बच्चों का सामान लिए लोग ट्रेन पकड़ने के लिए बेताब दिखे। फुटओवर ब्रिज पर भी यात्रियों की आवाजाही का दबाव बना रहा। सुरक्षा कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।

डीयू के सत्यवती कॉलेज में छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप, महिला आयोग ने प्रिंसिपल से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में एक छात्रा द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वत संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने और निष्पक्ष व समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्योरा (एक्शन टेकन रिपोर्ट) संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ मांगा है। साथ ही आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने कॉलेज प्रशासन को परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सक्रिय और प्रभावी बनाने और यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कालेज में जरूरी संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएं।

संक्षिप्त समाचार

मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक 18 नवंबर को होने की संभावना

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर को अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक



कर सकते हैं। इस दौरान उनसे शासन, सुधारों और कल्याण एवं विकास योजनाओं के संबंध में महिलाओं और युवाओं तक पहुंच बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। यह बैठक उस जारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मंत्रियों को सरकार के सामने आने वाले मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री 18 नवंबर की शाम को वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के तुरंत बाद अपनी मंत्रिपरिषद के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में शासन, सुधारों, कल्याणकारी और विकास योजनाओं के बारे में महिलाओं और युवाओं तक पहुंच बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक, जिसे चिंतन शिविर कहा गया था सितंबर में हुई थी। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर सरकारी योजनाओं के वितरण तंत्र (डिलीवरी मैकेनिज्म) को और कैसे बेहतर बनाया जाए।

संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी बर्दाश्त नहीं: शाह ने दिल्ली पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई को और मजबूत करने का निर्देश दिया. उन्होंने राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आस-पास के इलाकों में चल रहे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक समन्वित रणनीति बनाने पर बल दिया. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में चार घंटे तक चली हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने सीनियर पुलिस अधिकारियों से ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज से निपटने और उभरती सिक्योरिटी चुनौतियों का ज्यादा असरदार जवाब देने के लिए बड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (स्टैंडर्ड) बनाने को कहा. गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस और पड़ोसी एनसीआर शहरों में उनके समकक्षों के बीच ज्यादा समन्वय बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. ताकि क्रिमिनल लोगों को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का फ़ायदा उठाने से रोका जा सके. प्रस्तावित कोऑर्डिनेशन सिस्टम से इंटेलिजेंस-शेयरिंग मजबूत होने, ऑपरेशनल रिस्पॉन्स बेहतर होने और इंटर-स्टेट या इंटर-सिटी मौजूदगी वाले क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ जॉइंट एक्शन में मदद मिलने की उम्मीद है. मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर टीएस संधू, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए. मीटिंग की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि मीटिंग में नेशनल कैपिटल में मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मौजूदा पुलिसिंग इंतजाम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपायों का रिव्यू किया गया. अमित शाह ने पुलिसिंग स्ट्रेटेजी को मजबूत करने और संगठित आपराधिक नेटवर्क, खासकर जो नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, उनसे निपटने के लिए ज्यादा असरदार संस्थागत तरीका बनाने की जरूरत पर जोर दिया. छठ पूजा का त्योहार नजदीक आने पर गृह मंत्री ने पूरी दिल्ली में सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम का भी जायजा लिया. इस त्योहार को मनाने के लिए लाखों भक्तों के राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 से ज्यादा तय घाटों पर आने की उम्मीद है. कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी हो गया है.

मौत का डर नहीं: धमकियों के बीच बांग्लादेश लौटना चाहती हैं शेख हसीना, बोलीं- अपनी मिट्टी में मरना पसंद करूंगी

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि गिरफ्तारी, जेल या जान जाने का खतरा उन्हें ढाका लौटने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से दूर रहने के बजाय,



वह अपनी मातृभूमि में मरना ज्यादा पसंद करेंगी। आईएएनएस को दिए एक विशेष ऑडियो इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि जो उन्हें सही लगता है, उसे करने से उन्हें कभी डर नहीं रोक पाया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी राजनीतिक अनिश्चितता और अपनी सुरक्षा को लेकर खतरों के बावजूद वह बांग्लादेश लौट चुकी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'देखिए, मैं खतरों को अच्छी तरह समझती हूं। हो सकता है कि पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वे मुझे जेल भेज सकते हैं। यहां तक कि वे मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इन सभी संभावनाओं के बारे में सोच लिया है। लेकिन, आपको पता है, मैंने बहुत पहले ही अपनी निजी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। 1981 में सैन्य शासन के बावजूद मैं बांग्लादेश लौटी थी। फिर 2007 में भी मैं लौटी, जबकि मुझे पता था कि सेना समर्थित सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैंने जेल का सामना किया है और मेरी जान लेने की कई बार कोशिशें भी हुई हैं। जो मुझे सही लगता है, उसे करने से मुझे कभी डर नहीं रोक पाया।' बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताते हुए हसीना ने कहा कि देश एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आम लोग परेशान हैं और कई परिवारों के घर तथा आजीविका छिन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने जो मुश्किलें झेली हैं, उन्होंने उनके लौटने और लोगों के साथ खड़े होने के संकल्प को और मजबूत किया है, भले ही इससे उनकी जान को खतरा क्यों न हो। वहीं, बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर हसीना ने कहा, 'आज मेरा देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है। आम लोग तकलीफ झेल रहे हैं और परिवारों के घर और रोजी-रोटी छिन रही है। जब मेरे लोग इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकती हूं? मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताया है। मेरे साथ चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूं। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की मिट्टी पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।'

एलिस हुआंग चीनी जासूस हैं या नहीं: अब तक तय नहीं कर पाया अमेरिकी न्याय विभाग

वॉशिंगटन, एजेंसी। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से कथित संबंधों को लेकर चर्चा में आईं एलिस हुआंग के चीनी जासूस होने के आरोपों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने गुरुवार को कहा कि जांच में अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि एलिस चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थीं या नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लांश से एलिस हुआंग पर लगे चीनी जासूस होने के आरोपों को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ब्लांश ने कहा कि न्याय विभाग, वह खुद या एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एलिस हुआंग की भूमिका को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि एलिस चीनी सरकार की ओर से काम कर रही थीं या नहीं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि न्याय विभाग सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड की गतिविधियों की जांच कर रहा है। यह जांच अमेरिकी वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कंपनी एनवीडिया के एडवांस चिप खरीदकर उन्हें आगे चीन भेज रही थी। ब्लांश ने कहा कि उन्हें इस मामले की जांच करने की वाणिज्य विभाग की क्षमता को लेकर कोई चिंता नहीं है। एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित मेगास्पीड से जुड़ी एक कारोबारी हैं। इससे पहले आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चीनी खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों के कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उन पर नजर रख रही थीं। हालांकि, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के ताजा बयान से साफ है कि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।



मैं बहुत घटिया इंसान हूं': इस्तीफे से पहले जेनसन नेकही थी ये बात

वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। निजी संबंधों को लेकर सामने आए आरोपों के बीच कंपनी के बोर्ड ने बुधवार देर रात हुई बैठक में उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्तीफे से पहले हुआंग ने खुद को बेहद निराश बताया और कहा कि उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता नहीं है। रिपोर्ट में घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि कई हफ्तों तक आरोपों का खंडन करने और पद पर बने रहने की कोशिश के बाद बुधवार रात हुआंग ने हार मान ली। कंपनी में उनके काम करने का तरीका भी बदल गया था। वह पहले की तरह फैसले लेने और हर चीज पर नजर रखने के बजाय अब 'जो भी हो' और 'मुझे परवाह नहीं' जैसे वाक्य कहने लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में उनसे बात करने वाले लोगों ने बताया कि जेनसन हुआंग खुद को लेकर काफी कठोर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर खुद को 'बहुत घटिया इंसान' कहा। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने साथ क्या होगा, इसकी परवाह नहीं है। उनकी मुख्य चिंता अपनी पत्नी को लेकर है। साथ ही वह नहीं चाहते कि सार्वजनिक रूप से उनसे जोड़ी जा रही महिलाओं की जिंदगी भी प्रभावित हो। अक्तूबर के आखिर में खबरें सामने आई थीं कि हुआंग के चीन की कथित जासूस एलिस हुआंग से करीबी संबंध थे। बोर्ड में लंबे समय से कंपनी से जुड़े निवेशक, कारोबारी साझेदार और हुआंग के करीबी लोग शामिल थे। हुआंग ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं की है। कंपनी के भीतर भी 2025 के आखिर से उनसे इस बारे में सवाल किए जा रहे थे। सीईओ के तौर पर दिए गए अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने ब्लूमबर्ग से कहा था कि एलिस हुआंग के साथ उनके संबंध चीन के ग्राहकों और अधिकारियों के साथ सामान्य कारोबारी रिश्तों जैसे थे। हालांकि, 6 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच रोमांटिक संबंध थे।



आसमान में फिर हड़कंप; मेरे पास बम है... चिल्लाते हुए कॉकपिट में घुसा यात्री, पायलट ने भेजा हाईजैक अलर्ट

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। न्यू जर्सी के नेवार्क से लुइसियाना जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में एक यात्री ने कथित तौर पर बम होने की धमकी दी और कॉकपिट में जबरन घुसने की कोशिश की। घटना के बाद विमान में अफरा-तफरी मच गई। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) के अनुसार, इस घटना के चलते हाईजैक अलर्ट जारी किया गया। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

उड़ते विमान में दी बम की धमकी: फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 2174 सोमवार रात न्यू जर्सी के नेवार्क से न्यू ऑरलियन्स जा रही थी। इसी दौरान यात्री रोनी अलेक्जेंडर गोमेज-अल्बर्टो ने कथित तौर पर विमान में बम होने का दावा किया और कॉकपिट की ओर जबरन घुसने की कोशिश की। विमान में उस समय 46 यात्री और चालक दल के छह सदस्य मौजूद थे। आरोपी की इस हरकत के बाद विमान की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई। यात्री की कथित हरकत के कारण हाईजैक अलर्ट जारी हुआ। हालांकि, विमान के पायलटों ने औपचारिक रूप से हाईजैक घोषित किया था या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान में एक यात्री ने बाधा उत्पन्न करने वाली हरकत की थी। हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से न्यू ऑरलियन्स के लुइस आर्मस्ट्रांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। वहां स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के



अधिकारी पहले से मौजूद थे। विमान के गेट पर पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ आतंकित करने और आगजनी की योजना के बारे में झूठी जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। प्रत्येक मामले में 5 लाख डॉलर का बांड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उसे भगोड़े के रूप में भी हिरासत में रखा गया है, जिसके लिए कोई जमानत राशि निर्धारित नहीं की गई है। गिरफ्तारी के बाद आईसीई ने आरोपी के खिलाफ हिरासत संबंधी औपचारिक आदेश भी जारी किया।

दो बार अमेरिका से निकाला जा चुका आरोपी: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक, आरोपी गोमेज-अल्बर्टो होंडुरास का नागरिक है। उसका पहले भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रिकॉर्ड रहा है। इसमें बम की धमकी देने, आतंकित करने की धमकी देने और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का आव्रजन नियमों के उल्लंघन का भी लंबा इतिहास रहा है। उसे दो अलग-अलग मौकों पर अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है और तीन बार गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद जनवरी 2020 में एक आव्रजन न्यायाधीश ने उसे आगे की निर्वासन प्रक्रिया पूरी होने तक आईसीई की हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।

इस घटना के पीछे आरोपी का मकसद क्या था, अधिकारियों ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसका न्यू ऑरलियन्स से कोई संबंध था या वह किसी विशेष उद्देश्य से वहां जा रहा था। जांच एजेंसियों ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपी कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल हुआ था या नहीं और विमान में मौजूद यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों ने किस तरह स्थिति को संभाला। घटना में किसी के घायल होने की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

फायदों के बावजूद अटका पुलिस का बड़ा रिफॉर्म सतीश गोलछा के जाने के बाद ठप पड़ा मामला

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई पुलिस की तर्ज पर दिल्ली पुलिस में भी जांच और कानून-व्यवस्था की टीमों को अलग-अलग करने की कवायद पूर्व पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के हटते ही फिर ठंडे बस्ते में चला गया।

बताया गया कि कम समय में दिल्ली पुलिस में कई बेहतर बदलाव लाने वाले गोलछा ने इस विषय पर भी 10 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की की थी और उन्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उनको आयुक्त पद से हटा देने पर यह मामला ठप पड़ गया है।

इस तरह की व्यवस्था अब तक केवल मुंबई पुलिस में है। दिल्ली में भी पिछले एक दशक में इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए दो से तीन बार प्रयास किए गए। कुछ जिलों के कुछ थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जांच और कानून व्यवस्था को अलग-अलग भी किया गया। कई महीनों तक यह सिलसिला चला भी, लेकिन पुलिसकर्मियों की भारी कमी



और आए दिन दिल्ली में अचानक धरना प्रदर्शन होने से यह व्यवस्था लागू कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। गोलछा ने बेहतर पुलिसिंग के लिए इस नियम को हर हाल में लागू करने का मन बना लिया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में एक-एक महिला थाना खोलने, साइबर अपराधियों के शिकार पीड़ितों की शिकायत पर तुरंत एफआइआर दर्ज करने, मकोका सेल बनाने, आपरेशन साय हाक शुरू करने जैसे निर्णय गोलछा द्वारा लिया गया बेहतर कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस में हमेशा से पुलिस बल की भारी कमी रही है। इस नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करना तभी संभव हो पाएगा जब थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर कम से कम दोगुनी की जाए अन्यथा, दोनों टीमों को अलग करने में व्यावहारिक परेशानियां आ सकती हैं।

परिसीमन विधेयक में शामिल हो सकता है शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त लोकसभा सीटों वाला फॉर्मूला, क्या बोली कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना पर विचार कर रही है ताकि परिसीमन विधेयक, 2026 को पारित कराया जा सके। सरकार के अनुसार, यह विधेयक महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने से जुड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्र को अपने पास मौजूद संख्याबल पर पूरा भरोसा है और उसके पास जरूरत से कम से कम 15-16 वोट ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या उसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने हेतु सरकार को 361 वोटों की जरूरत है। 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें खाली हैं। परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। सरकार का यह प्रस्तावित कदम ऐसे समय में आया है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल हासिल करने में विफल रहा था। संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।अप्रैल में विपक्षी दलों खासकर दक्षिण भारत के दलों के साथ हुई बातचीत में सरकार ने कहा था कि वह सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहे। इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना था, क्योंकि सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं उद्योग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिवंगत डॉ.जसवंत सिंह यादव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बहरोड विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव के निधन पर अलवर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभानी श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने शोक संतृप्त परिवारजनों का ढाढ़स बंधाया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, तिजारा विधायक महन्त बालकनाथ, डीडवाना विधायक युनूस खान, नगर निगम महापौर सुमनलता अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत व रोहिताश शर्मा, पूर्व विधायक अशोक परनामी, जयराम जाटव व बनवारी लाल सिंघल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

राज्यपाल ने हैरीकॉन-2026 के तीसरे संस्करण के कार्यक्रम में की शिरकत

चिकित्सा क्षेत्र के उत्तरोतर विकास हेतु अनुसंधान एवं नवीन तकनीक का प्रयोग आवश्यक- राज्यपाल बागडे



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर/अलवर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को टेल्को सर्किल स्थित हरीश हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आयोजित हैरीकॉन-2026 के तीसरे संस्करण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवित शुभारम्भ किया।

राज्यपाल बागडे ने चिकित्सा शिक्षा के अनुसंधानों एवं नवीन आयामों के लिए आयोजित हैरीकॉन-2026 के तीसरे संस्करण के आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में केवल क्लिनिकल दक्षता के साथ बल्कि नवीन शोधों की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्रा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का है, इससे मरीजों के उपचार में काफी सुगमता हो रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धति में मशीनें सहायक सिद्ध तो हो सकती हैं लेकिन चिकित्सकों का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं एवं भावनाएं चिकित्सकीय परामर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

राज्यपाल बागडे ने कहा कि एक अच्छे चिकित्सक के लिए किताबी ज्ञान के साथ-साथ मरीज के साथ संवेदनशील रहकर समुचित उपचार किया जाना चाहिए। इससे चिकित्सा व्यवस्था की बेहतरी के साथ-साथ मरीज का चिकित्सा व्यवस्था व चिकित्सक में विश्वास प्रगाढ़ होता है। उन्होंने कहा कि रोगों से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए, जिसमें योग एवं हमारी परम्परागत भोजन पद्धति को शामिल किया जाना चाहिए।

इस दौरान उन्होंने पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति का फीडबैक लेने के साथ टीबी मुक्त व नशा मुक्त राजस्थान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

राजस्थान संपर्क 181 पर परिवादियों से सीधे जुड़े मुख्य सचिव, मौके पर दिए समाधान के निर्देश

विद्यालयों में सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

शहरी और ग्रामीण सेवाओं में शिकायतों का निस्तारण हुआ तेज, प्रगति पर मुख्य सचिव ने जताई प्रसन्नता

आवाज़ ए तसनीम





जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को राजस्थान संपर्क 181 केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वीडियो कॉल पर पाँच परिवादियों की समस्याएँ सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

सीकर जिले के एक विद्यालय में छात्राओं के साथ अनुचित स्पर्श की शिकायत पर मुख्य सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाए।

जयपुर जिले के शंकर लाल यादव ने कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने नवजात की देखभाल से जुड़ी समस्या बताई। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉल पर ही संबंधित चिकित्सा अधिकारी को नवजात की समुचित देखभाल और केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने को कहा।

दौसा के एक परिवादी ने जन आधार में आय प्रमाणपत्र का विवरण अद्यतन करने में देरी की शिकायत की। मुख्य सचिव ने मौके पर उपस्थित आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक को प्रकरण की जांच करने और जन आधार से जुड़ी सभी शिकायतों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रसोई गैस कनेक्शन के स्थानांतरण में देरी और एक छात्रा को अर्द्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने की शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने को कहा।

मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और शिकायतों के निस्तारण में आई तेजी तथा परिवादियों की बढ़ी संतुष्टि पर प्रसन्नता व्यक्त की। 13 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले निरीक्षण के बाद शहरी और ग्रामीण सुविधाओं की सभी 27 श्रेणियों में औसत निस्तारण समय घटा और 23 श्रेणियों में परिवादियों की संतुष्टि बढ़ी। नगरीय निकायों में निस्तारण का औसत समय 18 से घटकर 12 दिन और ग्रामीण पेयजल सेवाओं में 16 से घटकर 12 दिन रहा। इन सेवाओं में परिवादियों की संतुष्टि दर क्रमशः 9.37 और 4.82 प्रतिशत अंक बढ़ी।

'कृष्ण-राधा से रणभूमि तक' कार्यक्रम सनातन संस्कृति को मजबूती देने वाला

बृज क्षेत्र से मेरा गहरा नाता, संगीतमय प्रस्तुति ने जीवंत की भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा



आवाज़ ए तसनीम

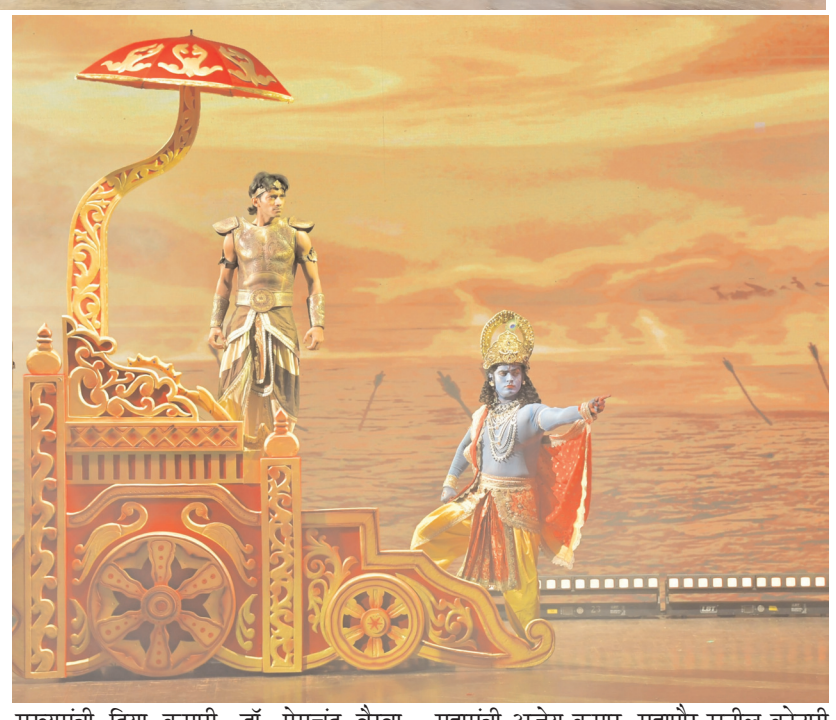

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बिड़ला सभागार में लेखक एवं कलाकार मनोज मुंतशिर की विशेष लाइव म्यूजिकल प्रस्तुति 'कृष्ण-राधा से रणभूमि तक' कार्यक्रम को देखा।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात अपने संबोधन में कहा कि ईश्वर के प्रति व्यक्ति जिस श्रद्धा से अपने भाव अर्पित करता है, उसे उसी अनुसार फल मिलता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत मंचन किया गया है। इसके लिए सभी कलाकार और इसके आयोजक बधाई के पात्र हैं तथा इस प्रकार की प्रस्तुति से हमारी सनातन संस्कृति और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अष्ट छाप के कवि गोविंद स्वामी जी और बृज क्षेत्र से उनका गहरा नाता है। बृज में समय बिताकर भगवान कृष्ण की लीलाएं आज भी देखने को मिल जाती हैं।

मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सांसद मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, महापौर सुनील कोठारी सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श अपनाने का किया आह्वान, राज्यपाल बागडे ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर) पर बधाई और शुभकामनाएं दी है।

बागडे ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस जल, जंगल और जमीन के लिए प्रतिबद्ध आदिवासी कल्याण की प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श हमारी धरोहर हैं। बिरसा मुंडा ने जनजाति गौरव, जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसी से वह जनजातीय गौरव का प्रतीक बने।

राजस्थान में 36,054 गांवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण, 19 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज 'स्वामित्व कार्ड'

शासन सचिवालय में शनिवार को स्वामित्व योजना प्रगति की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों और जिला कलेक्टर को दिए दिशा-निर्देश



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के साथ 'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की समीक्षा बैठक 25 नवंबर को प्रस्तावित है। इसके क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में स्वामित्व योजना की प्रगति पर समीक्षा की।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को अपनी सम्पत्ति के आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की स्पष्ट सीमाओं और आधिकारिक अभिलेखों से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों में कमी तथा पारदर्शिता बढ़ी है।

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगा राम ने योजना के विभिन्न चरणों की उपलब्धियों एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि प्रदेश के अधिसूचित आबादी के 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। यह कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। प्रदेश में अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 27 हजार 705 गांवों का जमीनी सत्यापन पूरा किया जा चुका है। इससे संपत्तियों के वास्तविक एवं सीमाओं के निर्धारण में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीसी के जरिए चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

बैठक में मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के शेष कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे किया गया है। बैठक में शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन टी. रविकान्त, भू-प्रबन्ध आयुक्त अल्पा चौधरी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीसी के जरिए सभी जिलों से जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारी जुड़े।

प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

9-10 दिसम्बर को जयपुर में सांस्कृतिक संध्या और मुख्य कार्यक्रम- मुख्यमंत्री भजनलाल

प्रदेश की विकास यात्रा में प्रवासी राजस्थानी महत्वपूर्ण भागीदार

प्रवासी राजस्थानी दिवस अपनी जन्मभूमि से जुड़ने का अवसर

8 दिसम्बर को झुंझुनूं में शेखावाटी हेरिटेज मीट

आवाज़ ए तसनीम





जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ऐसे में प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रदेश के प्रवासी राजस्थानियों के लिए अपनी जन्मभूमि से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और निवेश की संभावनाओं से परिचित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर आएंगी शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां

उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध कला-संस्कृति और स्थापत्य की पहचान हैं, इन्हें वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवासी राजस्थानी दिवस के तहत आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 8 दिसम्बर को झुंझुनूं के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सीकर, झुंझुनूं और चूरू के प्रमुख प्रवासी राजस्थानियों, उद्योगपतियों और हवेली मालिकों को आयोजन से जोड़ने के निर्देश दिए।

देश-विदेश के विशेषज्ञों की भागीदारी हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 दिसम्बर को शेखावाटी हेरिटेज मीट के बाद 9 दिसम्बर को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। वहीं, 10 दिसम्बर को जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने आयोजन में देश-विदेश के विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक तारावंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादक: रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिस: 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडी: tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइट: www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।